



EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 27 December 2025

'बालवीर' वैभव की कीर्तिमान से मित्रता, सपनों से साझेदारी

बल्ले और गेंद के प्रति समर्पण से फलक पर चमका समस्तीपुर का 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

उपलब्धि

अजय सिंह • जकार्ता

बल्ले : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। बिहार के कैम्पूर के 11 वर्षीय कमलेश को मरणोपरान्त पुरस्कार मिला, उसने नदी में डूबने तक बच्चे को बचाने में अपनी जान नोछ दी थी। वहीं उम्र के नौ साल के बहादुर अजय राज ने नदी किनारे मगसच्छ से अपने पिता को जान बचाई थी।

समस्तीपुर जिले के ताजपुर में उम्र दिनों स्कूल की घंटी से पहले बेटे से सामान बदती गैंग की टुकड़-टुकड़ सुराई चुराई थी। सुबह-सुबह जाग पड़ने के लिए बच्चों के कपड़ों के अंदर धातु की छिपी थी, जो घर की छत पर एक बच्चा हेलमेट-गैंग चुराते पिता को गैंग पर औरतों पर प्रहार करता था। बच्चे बचते तो कभी स्टेट हद्दवां बिना उम्र चक्र जते, तो सत आँसू बच्चा गैंग के स्वयं को

- कैम्पूर के 11 वर्षीय कमलेश को मरणोपरान्त पुरस्कार, बच्चे को बचाने में गंगा की थी जान
- वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई

वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि

- 12 वर्ष 264 दिन की उम्र में संजोती में फलंग
- क्रिकेट हजारे ट्राफी में 64 गैंगों में 190 रन
- आशीष टाल 2025 में 38 गैंगों में 101 रन
- अजय - 19 एशिया कप में 95 गैंगों में 171 रन
- युव टैस्ट में 62 गैंगों में 104 रन
- मुख्यमंत्री अली ट्राफी में 61 गैंगों में 108 रन
- गार्डिया टाला एशिया कप में 42 गैंगों में 144 रन



नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और कमलेश। (मरणोपरान्त) के पिता दुर्गाजी कुमार • हे

और आने की कल्पना कर हवा में बल्ले चलता रहता। पिता के संघर्ष, लगान और अटूट विश्वास के दम पर आँसू में बड़े सपने और दिल में क्रिकेट का जुनून लिए वैभव सूर्यवंशी के पापा अजय कुछ सैनिकों के तौर पर पंजाब और क्रिकेट के प्रति समर्पण। 14 वर्षीय वैभव को उसी समर्पण का सम्मान प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में मिला, जब राष्ट्रपति ने उन्हें इससे अवगत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैभव को बतलाया कि वे वैभव और उनके माता-पिता से मिलना भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव को बधाई दी। इस उम्र तक पहुंचने पर अजय जिस खिलाड़ी की प्रतिभा सबको

अस्फूर्तचिंत कर रही है, उसके पीछे संघर्ष की लम्बी कहानी है। बचपन आम बच्चों से अलग। खिलाड़ी के स्वभाव पर हाथों में बल्ले और गैंग पर एकदम निराला। माँ की टुकड़ा और विकास पित्त के घरेले के बच्चे घर की सीमित सुविधाओं में गहनतमी छुम्बे की तरह दुःख भरोते सपने। छोटी उम्र में ही वैभव ने

स्वयं को तब दिनचर्या में बांध लिया था। पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाना जल्दी सीख लिया। धुम में अगसा, अकसने से जुझना और बाद-बाद स्वयं को बेकार साबित करना, यही दिनचर्या बन गई। दिन-दुनिया के भर्नचर पर बिहार के चमकने वाले इस 'बालवीर' को चमकने के साथ हजारी प्रेरणाएं जुड़ीं।

भाई को बचाने के लिए स्वयं दे दी जान, 'बालवीर' के लिए सम्मान लेते पिता की आंखें भर आईं

संवाद सूर्यवंशी, जामुगम • मोहनियां (कैम्पूर) : अपने बड़े भाई को बचाकर स्वयं मौत के मुंह में चले गए बच्चे को मरणोपरान्त जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो माता-पिता की आंखें भर आईं। कैम्पूर जिले के मोहनियां थान क्षेत्र स्थित भद्रवर्षिया गांव के कमलेश के माता-पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को यह सम्मान ग्रहण किया।

घटना इसी वर्ष 25 जुलाई को है। दुर्घटना जांचबाल का पुत्र कमलेश (11) अपने बड़े भाई पवन (13) के साथ गांव के ही खिलाडलव में पढ़ते मया था। कहां से दोनों दुर्घटना नदी में डूबने वाले गये। इसी दौरान पवन बचने सपने में डूबने लगा, पर असाधारण बौद्धि नहीं था, जो बच सके। वह देख कमलेश ने अपने भाई को बचाने के लिए

मोहनियां के 11 वर्षीय कमलेश के पिता व माता तै आंखें दिखाने पुत्र के लिए सम्मान ग्रहण करते समय भर आईं

उसका कर्तव्य भरो अना-पना नहीं चला। उसका झोला नदी किनारे पड़ा था। पसरीअसाधारण की टांग ने बचने प्रयास के बाद अगले दिन उसका शव दूधकर निकाला। कमलेशने पढ़ने में मेधावी था, माता-पिता को उससे बहुत असा था। अपने बड़े भाई को जान बचाने के लिए स्वयं को जेकिम में डालते हुए अपने अपनी बहादुरी भी साबित कर दी। उसके इस साहसिक कृत्य की चर्चा पूरे जिले में हुई। भारत सरकार ने उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय किया। उसके पिता दुर्गाजी जावसवाल का माता निता देवी की आंखें दिखाने पुत्र के लिए सम्मान ग्रहण करने की बच्चा मिला, पर स्वयं मौत का शिकार हो गया। पवन ने घर जाकर अपने पुत्र की बाँटों को वह सम्पत्ति कर रहे हैं। वह देख कमलेश गांव के लोग रोड़े आए, लेकिन सखीस खबर • जामुगम सिटी • वन 17

वैभव को रोज समस्तीपुर से पटना बस से लाते थे पिता

बढ़ते कदम

जामुगम पटना : वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट का जुनून देख पिता संजोय सूर्यवंशी ने अकादमी में अगसा करा खेल में निहार लाने का मन बना लिया। समस्तीपुर में खेल संभावना न देख रोज पटना आने की योजना बन गई। तीन भाइयों में बीच वाले बेटे के लिए संघर्ष की यात्रा सुरु के निकलने से पहले शुरू होने लगी। रात तीन बजे उठ मां आरती सूर्यवंशी खान बना टिफिन तैयार करती, पिता सुनह पांच बजे बेटे को लेकर घर से निकल जाते।

राजधानी के संघर्षक में जेएक्स अकादमी के प्रशिक्षक व वैभव के प्राथमिक कोच मनोय ओझा बताते हैं, वैभव के पिता उसे रोज समस्तीपुर से बस से पटना लाते थे। तब उम्र नौ से 10 साल रही होगी। जब तक वह अगसा करता, पिता मैनपन पर रहते। तब वो एक दिन में 500 से अधिक गेंदें



नई दिल्ली में वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी • सी हे

खेलता था। बीच में समय देख उसे खान खिलाते। समस्तीपुर से आने-जाने में एक दिन पूरा लग जाता, ते वो एक दिन छोड़कर पटना आने लगा। उसमें किसी भी छोटे वा बड़े खिलाड़ी से अधिक परिश्रम करने को लालक रही। उसने कभी हालत को देख नहीं

दिया, यल्लि आने मेहनत को और तेज कर दिया। चैनी एवं कर्द चयनकर्ताओं को उसकी यल्लेखजो का वीहिवो बनाकर भेजा। समय के साथ मैनपन पर उसका आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। विजय हजारे में शुक्रवार को खेल गया मैन राष्ट्रपति से सम्मानित होने के कारण वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल सके। वे 29 दिसंबर को मेघालय के खिलाफ गैंगों में होने वाले मुकाबले में वे उपलब्ध होंगे। इसके बाद अंडर-19 श्रृंखला के लिए भारत वनम साठय अठोका सीरीज में भाग लेने के लिए वे रवाना हो जायेंगे।

Dainik Jagaran Page No-1

शवन सिंह ने आपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन हमलों के बीच सैनिकों तक पहुंचाई थी मदद

वीर बाल दिवस

संजोय गुला • जकार्ता

नई दिल्ली : वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 वर्षीय की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस साल दो बच्चों को मरणोपरान्त यह पुरस्कार दिया गया। उनके पुरस्कार माता-पिता ने लिए। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सभी पुरस्कार साहसिक कृत्यों और खेल, विज्ञान व कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पुरस्कार बच्चों की प्रशंसा की और कहा कि वे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

जामुगम में फिरोजपुर के 10 वर्षीय शवन सिंह ने आपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण साहस का परिचय देते हुए ड्रोन हमलों की स्थिति में भी सैनिकों तक मदद पहुंचाई थी। वहीं, उत्तर प्रदेश के नौ साल के बहादुर अजय राज ने नदी किनारे मगसच्छ



सेना के जखाने तक दूध, चाय व अन्य सामान पहुंचाता शवन • • शेटवटी बीडिया



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार खसित करते हुए पवन सिंह। • गेट

से पिता को जान बचाई थी। बराबकी की पुत्रा को किरसानों के लिए कृषि प्रदूषण कम करने वाली मशीन बनाने के लिए सम्मान मिला। द्वारछंड की 14 वर्षीय फुटबालर अनुष्का को हाल में अंडर-17 महिला फुटबाल टीम में शामिल किया गया है। तेलंगणा के मेडचल मलकागिरी निवासी 16 वर्षीय विश्वनाथ ने दुनिया के सार महाद्वीपों को सबसे ऊंची चोटियों (सैन समिट्स) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। यह ऐसा करने वाले सबसे

कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतरोही हैं। केरल के रहने वाले 11 वर्षीय सिद्धन के दो मित्र कर्तव्य की चोट में आ गए थे। सिद्धन ने सुझाव दिखते हुए लकड़ी की मदद से अपने दोनों मित्रों को बचाया। महाराष्ट्र निवासी 17 साल के अर्धन सार्थी को विज्ञान श्रेणी में बाल पुरस्कार मिला है। मिजोरम के नौ वर्षीय हम्मनेत यूट्यूब स्टार हैं, उनके चैनल पर दो करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं।

Dainik Jagaran Page No-IV

दीप्ति शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से बेटियों का सीरीज पर कब्जा

महिला टी-20

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। दीप्ति शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से भारतीय महिला टीम ने शुक्रवार को जीत के प्रतिक के साथ पांच मैचों की टी-20 सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। बुधवार के बाद वापसी करने वाली टीम (18/3) को फिरकी और एणुका सिंह ठाकुर की (21/4) की हार बापाती गेंदों ने श्रीलंका को गीसरे टी-20 में सात विकेट पर 112 (न पर रोक दिया। उसके बाद लक्ष्मी शेफाली (79) को तुफानी पारी से 13.2 ओवर में दो

विकेट पर 115 रन बनाकर हासिल कर लिया। आठ विकेट की जीत के साथ भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। चौथी मुकाबला इसी मैदान पर रविवार को खेला जाएगा। शेफाली ने लगातार दूसरा और करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। मंथाना (1) फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाई। शेफाली ने जॉममा (9) के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 और कप्तान हरमनप्रीत कौर (21) के साथ तीसरे विकेट के लिए अट्ट 48 रन जोड़े। शेफाली ने 42 गेंदों को अपनी पारी में 11 चौके और तीन छक्के जड़े। उन्होंने चौके के साथ टीम को जीत दिलाई।



दिसंबर के बाद अपना पहला टी-20 मैच खेल रही रेणुका ने नई गेंद से श्रीलंका के शीर्ष क्रम को झकझोर

दिया। उन्होंने फॉर्म में चल रही हसिनी परेरा (25) और हर्षिता (2) को एक ओवर में पवेलियन भेजा। उसके

08 विकेट से पराजित किया भारत ने श्रीलंका को तीसरे मुकाबले में 40 गेंद रहते गेंद में वर्मा ने पचास रन पूरे किए जो भारत की ओर से चौथा सबसे तेज अर्धशतक

79 रन की पारी शेफाली ने 42 गेंदों में 11 चौको और तीन छक्कों की मदद से खेली

तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को विकेट लेने के बाद जश्न मनाती दीप्ति शर्मा।

दीप्ति 150 विकेट वहजार रन बनाने वाली इकलौती

दीप्ति टी-20 में 150 विकेट लेने और 1000 या उससे अधिक विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर (पुरुष और महिला) बन गईं। वह 131 मुकाबलों में 6.09 की इकोनॉमी से 151 विकेट झटक चुकी हैं और 1100रन भी बना चुकी हैं। उन्होंने महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शॉट (151) के फटाफट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया।

(3), कविशा दिलहारी (20) और मल्लिका शेठानी (5) को अपनी फिरकी में फंसाया।

वर्ष 2025 में कुछ भी असाधारण नहीं रहा

लेखा जोखा

भारत अब अगले साल होने वाले मैचों को लेकर कर रही तैयारी

भारतीय हाकी के लिए कठिन साल, महिला टीम का प्रदर्शन चिंताजनक

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा)।

पिछले साल ओलंपिक कांस्य झोली में डालने के बाद 2025 भारतीय हाकी के लिए कुछ खाल नहीं रहा हालांकि पुरुष टीम ने लगभग एक दशक बाद एशिया कप जीता लेकिन महिला टीम के प्रदर्शन में निरंतर गिरावट चिंता का सच्य बन गई है।

भारतीय हाकी को यह शताब्दी वर्ष भी है लेकिन आठ बार की ओलंपिक चैंपियन टीम के लिए वर्ष 2025 में कुछ भी असाधारण नहीं रहा। इस वर्ष भारतीय हाकी को सबसे बड़ी उपलब्धि पुरुष टीम को राजगीर में एशिया कप में जीत रही जहां आठ साल बाद विजय जीतकर अपने अगले साल 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआइएच विश्व



कप का टिकट कटया। भारतीय टीम ने एक बार फिर उपमहाद्वीप में दबदबा बनाया और सबसे अच्छी बात यह रही कि 15 गोल दाने जबकि सिर्फ दो भयंसे। फाइनल में भारत ने मत चैंपियन एशियन कोरिया को 4 . 1 से हराया

जिसमें दिलीप सिंह, सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने गोल किये। इससे पहले एफआइएच प्रो लीग में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हरमनप्रीत सिंह की टीम जो टीमें में आठवें स्थान पर रही और नीचे खिसकने से बाल बाल बची है। परंतु

विश्व कप के अलावा एशियाई खेलों पर होंगी नजरें

अजलन शाह कप में भारत की युवा टीम ने रजत पदक जीता। छह साल बाद टूर्नामेंट खेल रही भारतीय टीम फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर की टीम बेल्जियम से एक गोल से हारी। लेकिन गर कप्तान संजय के साथ युवा टीम गई थी जिसमें हरमनप्रीत और मनीष जैसे सीनियर नहीं थे। पुरुष जूनियर टीम ने इस महीने चेन्नई में जूनियर हाकी विश्व कप में नौ साल बाद कांस्य पदक जीता। भारत की नजरें अब अगले साल विश्व कप के अलावा जापान में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतकर लास एंजेलिस ओलंपिक 2028 में सीधे उपाह बनाने पर लगी होंगी।

की टीम बेल्जियम से एक गोल से हारी। लेकिन नये कप्तान डिफेंडर संजय के साथ युवा टीम गई थी जिसमें हरमनप्रीत और मनीष जैसे सीनियर नहीं थे। पुरुष जूनियर टीम ने इस महीने चेन्नई में जूनियर हाकी विश्व कप में नौ साल बाद कांस्य पदक जीता। कांस्य के मुकाबले में अर्जेंटीना से दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए भारत ने 4.2 से जीत दर्ज की।

भारत को निगाहें अब अगले साल विश्व कप के अलावा जापान में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतकर लास एंजेलिस ओलंपिक 2028 में सीधे उपाह बनाने पर लगी होंगी। दूसरी ओर तोक्यो ओलंपिक 2021 में चौथे स्थान पर रहने के बाद महिला टीम का प्रदर्शन लगातार खरबसे हुआ है और पिछले साल टीम पेरिस ओलंपिक के लिए ब्यालीकॉर्ड नहीं कर सकी थी।

अभियान

जांच में तेजी के साथ बढ़ गए तपेदिक के मरीज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक

दो वर्ष बढ़ाया गया तपेदिक उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

देश में तपेदिक (टीबी) उन्मूलन का अभियान अभी दो साल और चलेगा। जांच के दौरान बढ़े मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य साल 2025 से बढ़ाकर साल 2027 कर दिया है। केंद्रीय क्षय प्रभाग की जानकारी के अनुसार देश में अक्टूबर 2025 तक टीबी के 2077591 मरीज मिले। प्रति लाख के आधार पर साल 2025 में यह आंकड़ा 195 मरीज पर पहुंच गया, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 131 पर था।

स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी



राज्य को मिलेगी हर संभव मदद

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य को हर संभव मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कुछ रोग के प्रबंधन को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों के साथ ही मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान को चलाया जाएगा। बैठक में दवा विनियमन को मजबूत करने, निदान को बेहतर बनाने, अस्पताल प्रबंधन को पेशेवर बनाने, चिकित्सा शिक्षा क्षमता को बढ़ाने और टीबी मुक्त भारत की दिशा में तेजी से प्रयास के लिए काम किया जाएगा।

नड्डा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री व अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंचाने, मरीजों की संतुष्टि बढ़ाने, नियामक

निगरानी में सुधार करने और 2027 तक ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) को सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता के तौर पर खत्म करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

भारतीय दवाओं की बढ़ रही है विदेश में विश्वसनीयता : नड्डा

भारतीय दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ विदेश में विश्वसनीयता भी बढ़ रही है। यह कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। शुक्रवार को मंत्री ने मंत्रालय की सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही निवेदिता शुक्ला वर्मा के साथ भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आइपीसी) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि दुनिया के 19 देशों में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता मिल चुकी है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक पहल है।

12 लाख लोग आए, 19 करोड़ की बिक्री

सरस मेला

जागरण संवाददाता, पटना : बिहार सरस मेला में खरीदारी के साथ लोग राज्य के मशहूर व्यंजनों का भी स्वाद ले रहे हैं। 14 दिनों में 19 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है, 12 लाख से अधिक लोग मेला में आ चुके हैं।

गुरुवार को मेला में रिकार्ड डेढ़ लाख से अधिक पहुंचे और दो करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के स्टाल पर कटे-फटे व पुराने नोट भी बदले जा रहे हैं तो विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआइ), पटना के स्टाल पर मैनेजमेंट कोर्स में भविष्य की जानकारी दी जा रही है। बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों के लिए जीविका के सामाजिक विकास विद्या के द्वारा व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मोतिहारी से आए धर्मा जी के स्टाल पर घर-कार्यालय आदि



सरस मेला में मोतिहारी के स्टार्टअप धर्मा के उत्पाद के लिए ग्राहकों की भीड़। • जागरण

को स्वच्छ व खूशबूदार रखने की सामग्री और टिप्स दिए जा रहे हैं।

दीदी की रसोई समेत 50 स्टाल पर विभिन्न प्रदेशों के देशी व्यंजनों एवं मिठाइयों का स्वाद ले रहे हैं। सौ से अधिक स्टाल से हस्तशिल्प, कलाकृतियों, परिधान, गर्म कपड़े, रजाई, दोहरा, कंबल, चादर,

कालीन, रस, टेराकोटा, सेरामिक, फर्नीचर, कृत्रिम फूल एवं गहने, सुगंधित इत्र, अगरबतियां, कश्मीरी फल, मडूआ, बाजरा, जौ आदि के आटा, आचार, पापड़, अडवरी, दनवरी, आयुर्वेदिक पापड़, मालभोग और कतरनी चूड़ा, गुड़, लड्डू आदि की मिल रहे हैं।

सेवा क्षेत्र की मदद से निर्यात का बनेगा रिकार्ड

चालू वित्त वर्ष में **850 अरब डालर** के नए उच्च स्तर को छू सकता है कुल निर्यात, चुनौतियां बरकरार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सेवा क्षेत्र के सहयोग से चालू वित्त वर्ष 2025-26 में कुल निर्यात 850 अरब डालर के नए स्तर को छू सकता है। अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत 562 अरब डालर का निर्यात कर चुका है और चालू वित्त वर्ष समाप्त होने में अभी चार माह बाकी है। नए वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय निर्यात की रफ्तार और तेज हो सकती है। अगले साल चीन को छोड़कर दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत का व्यापार समझौता संभव दिख रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार वार्ता अंतिम चरण में है तो कनाडा व रूस के साथ भी व्यापार समझौते को लेकर वार्ता शुरू हो चुकी है।

खास बात यह है कि निर्यात के मोर्चे पर सरकार के सामने नए साल में कई चुनौतियां भी दिख रही हैं। अगले साल एक जनवरी से यूरोपीय संघ कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट

- चीन को छोड़ सभी बड़े देशों से व्यापार समझौते की संभावना से भी मिलेगा निर्यात को बल
- गुणवत्ता बढ़ाने के साथ निर्माण लागत में कमी से सप्लाय वेन में बढाई जा सकती है भागीदारी

562 अरब डालर का भारत निर्यात कर चुका है अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान

400 अरब डालर को पार कर सकत है सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष में

1 ट्रिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा है वाणिज्य विभाग ने 2030 तक

मैकेनिज्म (सोबैम) लागू करने जा रहा है, जिससे यूरोपीय देशों को स्टैल, एल्युमिनियम जैसे उत्पादों का निर्यात करना चुनौतीपूर्ण हो



वस्तु निर्यात में कोई वृद्धि होने की उम्मीद नहीं

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक गत वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने वस्तु और सेवाओं को मिलाकर 825 अरब डालर का निर्यात किया था। इनमें 438 अरब डालर का वस्तु तो 387 अरब डालर का सेवा निर्यात शामिल था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात कमोवेश पिछले वित्त वर्ष के स्तर पर ही दिख रहा है। दूसरी तरफ चालू वित्त वर्ष में सेवा निर्यात पहली बार 400 अरब डालर को पार करने जा रहा है और उसकी मदद से ही कुल निर्यात 850 अरब डालर पर पहुंच जाएगा।

जाएगा। सोबैम के तहत वस्तुओं के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन के हिसाब से यूरोप अलग से टैक्स लगाएगा। इसके अलावा अमेरिका

के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी भी चुनौती साबित हो सकती है। तमाम वैश्विक चुनौतियों और अमेरिका के 50 प्रतिशत शुल्क के

पिछले दो वर्षों में 20 से अधिक नए देशों को शुरू किया गया निर्यात

वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2030 तक देश के निर्यात को एक ट्रिलियन डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। व्यापार समझौते की वजह से अगले साल कई बड़े देश के बाजार भारत के लिए शुल्क मुक्त हो जाएंगे, जिसकी मदद से 2030 तक एक ट्रिलियन डालर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। श्रीवास्तव का कहना है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ निर्माण लागत में कमी करने की जरूरत है ताकि वैश्विक सप्लाय वेन में भागीदारी बढ़ाई जा सके। नए बाजार की तलाश शुरू हो गई है और पिछले दो साल में 20 से अधिक नए देशों में निर्यात शुरू हो चुका है।

बावजूद अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी दिख रही है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में कोहरे की संभावना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली में मध्यम कोहरे की संभावना जताते हुए 'पीली चेतावनी' जारी की है। विभाग के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आसमान पर पूरे दिन कोहरा छाया रहेगा और तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी।

आइएमडी के अनुमान के अनुसार, 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21-23 डिग्री

और न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री के बीच रहेगा। दोपहर में हवाओं की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो शाम के समय घटकर 0-5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे 28 दिसंबर को कोहरा और गहरा होगा और दृश्यता प्रभावित होगी। 28 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21-23 डिग्री और न्यूनतम 5-7 डिग्री रहने का अनुमान है। दोपहर बाद हवा की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी, जबकि रात में यह 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

बादल और हल्का कोहरा देखा गया। अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री और न्यूनतम 7.7 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं की औसत गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नागरिकों से अपील की है कि वायु गुणवत्ता में अस्थायी सुधार के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन जारी रखें। उन्होंने चेताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बिगड़ सकता है, घनी धुंध और कोहरे की आशंका बढ़ सकती है और प्रदूषण स्तर फिर बढ़ सकता है।

Jansatta Page No-3

गंभीर समस्या

श्वसन विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

कोविड के बाद प्रदूषण सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 दिसंबर।

राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के अधिकांश महानगरों की खराब हो रही आबोहवा के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत जिस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, वह वायु प्रदूषण है।

ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के श्वसन रोग विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात साल दर साल और बिगड़ेंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि देश में श्वसन संबंधी बीमारियों का एक बड़ा संकट धीरे-धीरे विकराल रूप ले रहा है, जो अभी न तो बड़े पैमाने पर

पहचाना गया है और न ही इसके समाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन)



की वायु प्रदूषण पर रपटें लगातार यह बताती हैं कि वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं, खासकर बच्चे, और विश्व के देशों के मौजूदा कानून अक्सर अपर्याप्त होते हैं।

केंद्र सरकार की विभिन्न रपट में भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण भारत के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य

और आर्थिक समस्या है। वर्ष 2025 में आई लैंसेट रपट के मुताबिक, वर्ष 2022 में भारत में प्रदूषण से करीब 17 लाख लोगों की मौत हुई। जिसमें 7.5 लाख मौतें जीवाश्म ईंधन के कारण थीं।

भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, जहां हवा में जहरीले तत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से काफी ऊपर हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गत मंगलवार को स्वीकार किया कि दिल्ली में लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से आता है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है।

ब्रिटेन में कार्यरत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा कि सांस संबंधी बीमारियों का यह छिपा हुआ संकट धीरे-धीरे गंभीर बाकी पेज 8 पर

Jansatta Page No-1

गंगा के उत्तरी क्षेत्र के तीन व दक्षिणी क्षेत्र के पांच एयरशेड बढ़ा रहे वायु प्रदूषण

अखिलेश ठीकरी • जगरण

कानपुर : बिहार में पांच ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता की स्थितियों को गंभीर बना रहे हैं। इसमें गंगा के उत्तरी क्षेत्र में तीन और दक्षिणी क्षेत्र में दो इलाके हैं। आइआइटी कानपुर ने बिहार में वायु गुणवत्ता यानी प्रदूषण की स्थितियों का संस्तर आधारित डेटा तैयार किया है, इसके अनुसार उत्तर बिहार के 21 और दक्षिण बिहार 16 जिलों के ऊपर प्रदूषित हवा के घने बादल बने हैं जो लगभग पूरे साल बिहार को हवा को खराब बना रहे हैं। इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारकों को पहचान कर पूरे राज्य की हवा को स्वच्छ-सुथरी बनाना जा सकता है।

आइआइटी के नवाब का एक शोधन भी बिहार सरकार के साथ साझा किया है। इन रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय जलन एनवायरनमेंटल सर्वेस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित किया गया है।

शहरों में वायु गुणवत्ता जंचने के उपाय पहले से लागू हैं लेकिन पहली बार देश में किसी राज्य को वायु गुणवत्ता का अकलन किया गया। आइआइटी कानपुर के प्रो. सविन्वन्द त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (अमृत) परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत अल्पकालिक संस्तर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एसएएनएन) लागू किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर राज्य के सभी विकासखंडों में 538 संस्तर लगाए हैं। जिससे हर पल को वायु गुणवत्ता का डेटा जुटाया जा रहा है। मौसम लॉगिंग और एअर डेटा माइनिंग का प्रयोग कर आइआइटी की टीम ने पूरे बिहार में पांच ऐसे एयरशेड की पहचान की है जहां वायु गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है। इसमें उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर से सटा है। यहां की हवात सबसे बदतर है। लगभग 90 प्रतिशत दिनों में लोग



अव्यक्तकर हवा में संसर लेते हैं। इस इलाके में कुल वार्षिक उत्सर्जन राज्य के अंदर तुलना में ज्यादा है। इस इलाके में दूध भट्टा इंडस्ट्री (1900), चोनी मिल (9) और मुजफ्फरपुर जिले में कंटी थर्मल पावर स्टेशन को मौजूदगी को वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है। वायोबास का जलन और प्रो-मानसू के दौरान पश्चिमी पंजाब और गोवालांज जिलों में जंगल में लाने वाली तेज आग भी पौरस 2.5 प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकती है।

प्री मानसू स्थितियाँ

जिले	पीएम 2.5 की मात्रा प्रति वर्गमीटर
गोपालगंज	74
पश्चिमी पंजाब	70
वैशाली	52

बिहार सरकार के सहयोग से अमृत परियोजना पर काम किया गया और फलती बार पूरे राज्य में वायु गुणवत्ता की पहचान हुई है। इस रिपोर्ट की मदद से वायु प्रदूषण के कारणों की पहचान कर समाधान किया जा सकेगा। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई है।

— प्रो.सविन्वन्द त्रिपाठी, डीन कोटक सूक्ष्म आक संरचनाविज्ञान, आइआइटी कानपुर

आइआइटी कानपुर के अध्ययन की मुख्य बातें

एयरशेड एक : उत्तर-पश्चिमी बिहार के नौ जिले शामिल हैं। कुल 23,939 वर्ग किमी का एरिया। मानसू के बाद और सर्दी के मौसम में पीएम 2.5 का औसत क्रमशः 165 और 210 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर था। मानसू बाद शिवहर और गोपालगंज में (175 माइक्रोग्राम) सर्वाधिक है। सर्दी में, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिलों में पीएम 2.5 सबसे ज्यादा 230 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर होता है, जबकि सीवान में (190 माइक्रोग्राम) सबसे कम होता है।

एयरशेड 2 : आठ जिलों में कुल एरिया 17,997 वर्गमी है। सबसे ज्यादा औसत पीएम 2.5 धनत सर्दी के मौसम में 187 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर) पलवल, इसके बाद पोस्ट-मानसू (131) और प्री-मानसू (54) रहा है। पोस्ट मानसू में पीएम 2.5 का स्तर समस्तीपुर (152), सर्दी के दौरान मेथुल और दरभंगा (220) और प्री मानसू के दौरान खगड़िया और मुझुर्नी (65) में ज्यादा था। सबसे कम धनत पोस्ट मानसू के दौरान खगड़िया (115) का रहा।

एयरशेड 3 : उत्तर पूर्वी बिहार। यह सबसे छोटा एयरशेड है, जिसका क्षेत्रफल 11,039 वर्ग किमी है। इसमें वार जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार हैं। इसमें पीएम 2.5 का धनत सर्दी के दौरान (176) पोस्ट मानसू (105) और प्री मानसू में (66) था। इसके अलावा, पोस्ट मानसू, सर्दियों और प्री मानसू मौसमों के दौरान जितनेवार किलेबग से प्राप्त चलत है कि कटिहार (118), अररिया (201), और किशनगंज (83) में ज्यादा धनत है।

एयरशेड 4 : दक्षिण-पश्चिमी बिहार। 21,152 वर्ग किमी में आठ प्रशासनिक जिले शामिल हैं। पोस्ट मानसू के दौरान मौसमी औसत पीएम 2.5 धनत 110 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर रहा है। सर्दी में 160 और प्री मानसू में 48 थी, जबकि पूरे एयरशेड में यह 106 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर पीएम 2.5 रहा है। बक्सर में पोस्ट मानसू (124), सर्दी में (173) और प्री मानसू (63) का स्तर रहा है।

एयरशेड 5 : दक्षिण-पूर्वी बिहार। आठ प्रशासनिक जिले शामिल हैं। कुल क्षेत्रफल 16,850 वर्ग किमी है। सर्दी में सबसे अधिक पीएम 2.5- 144 माइक्रोग्राम प्रति वर्गमीटर था। मानसू के बाद (98) और मानसू से पहले (44) का स्तर था। नालंदा जिले (मानसू के बाद 112 और सर्दियों में 173) का धनत था। मानसू के बाद शेखपुरा (102) और सर्दियों में भागलपुर (156) रहा है।

शोध को आसान बनाएगा 'परम रुद्र'

आइआइटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ, 39 पेटाफ्लाप्स है कुल कंप्यूट क्षमता

उपलब्धि

जागरण संवाददाता पटना: आइआइटी पटना में स्थापित अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटर परम रुद्र का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के अंतर्गत स्थापित परम रुद्र की शुरुआत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा, आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह, समन्वयक प्रो. सोमनाथ त्रिपाठी, नवीन कुमार और डा. चितरंजन सिंह मौजूद रहे।

अमितेश कुमार सिन्हा ने कहा कि "राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देशभर में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कंप्यूट क्षमता 39 पेटाफ्लाप्स है। जिनका उपयोग देश के 12 हजार से अधिक शोधकर्ता कर रहे हैं। शीघ्र ही विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में 10 और सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियां स्थापित की जाएंगी, जिससे कुल कंप्यूट क्षमता 100 से अधिक पेटाफ्लाप्स हो जाएगी। देश में सुपरकंप्यूटिंग इकोसिस्टम के निर्माण के लिए स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग तकनीकों जैसे एचपीसी प्रोसेसर,

देश के 12 हजार से अधिक शोधकर्ता कर रहे प्रयोग, जटिल कम्प्यूटिंग कार्य करने में सुविधा

प्रणाली के निर्माण में प्रयुक्त अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन देश में ही हुआ है



आइआइटी पटना में परम रुद्र सुपरकंप्यूटर के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा, आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह व अन्य। ● सौ: आइआइटी।

सर्वर, क्लिंट तकनीक, इंटरकनेक्ट, साफ्टवेयर स्टैक और स्टोरेज का विकास किया जा रहा है, जिससे डिजाइन, विकास और विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने यह बताया कि राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की यह संयुक्त पहल है।

प्रो. टीएन सिंह ने कहा कि यह

एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इससे बिहार और पूर्वांचल में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा तथा छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में जटिल कम्प्यूटिंग कार्यों को करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। परम रुद्र सुपरकंप्यूटिंग सुविधा एनएसएम के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसमें इस प्रणाली के निर्माण में प्रयुक्त

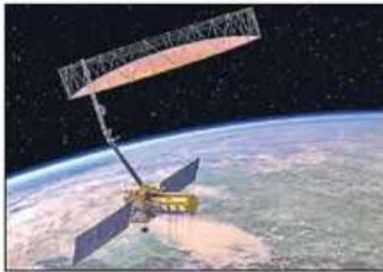
अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन देश में ही किया गया है। साथ ही, मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप सी-डैक द्वारा विकसित स्वदेशी साफ्टवेयर स्टैक का उपयोग किया गया है। इस 838 टेटाफ्लाप्स सुपरकंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना हेतु आइआइटी पटना और उन्नत संगणन विकास केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनएसएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस सुपरकंप्यूटर की कुल कंप्यूट क्षमता का एक हिस्सा निकटवर्ती शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ भी साझा किया जाएगा। कुल मिलाकर, यह सुपरकंप्यूटिंग सुविधा भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को एक नई गति प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।

पेटाफ्लाप्स क्या है: पेटाफ्लाप्स प्रोसेसिंग गति का विशाल मापक है। प्रति सेकंड फ्लोटिंग प्वाइंट आपरेशन (फ्लाप्स) सुपरकंप्यूटर की प्रदर्शन क्षमता को मापने की इकाई है। सामान्य कंप्यूटर के प्रोसेसर की कार्यक्षमता को मेगाहर्ट्ज इकाइयों में मापकर उसकी क्लाक स्पीड की गणना की जाती है।

Dainik Jagaran Page No-4

निसार : पृथ्वी की निगरानी हुई आसान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने संयुक्त रूप से इस मिशन को 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। निसार मिशन पृथ्वी पर भूमि परिवर्तनों की निगरानी के लिये प्रत्येक 12 दिनों में हाई-रिजॉल्यूशन



डाटा मुहैया कराएगा। यह भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होने वाली भूमि विकृति पर नजर रखेगा। उपग्रह फसल विस्तार और विकास चक्र जैसे कृषि पैटर्न की निगरानी करता है तथा मौसमी और जलवायु परिवर्तनों के कारण आर्द्रभूमि में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने सहित क्रायोस्फीयर गतिशीलता का अध्ययन होगा। उपग्रह ने उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें खींची थीं।

Hindustan Page No-21

अलबर्ट एक्का की असाधारण वीरता की गवाह बनी गंगासागर की लड़ाई



अलबर्ट एक्का का जन्म 1942 में आज ही झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। 1962 में गाइर्स ब्रिगेड की 14वीं बटालियन में भर्ती हुए। ट्रेनिंग के ही दौरान ही उन्हें लांस नायक बना दिया गया। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी बटालियन को गंगासागर में मजबूत पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। यह ढाका जाने वाले एक प्रमुख रेलवे मार्ग पर स्थित था। तीन दिसंबर को 14 गाइर्स ने दुश्मन की चौकियों पर हमला किया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी एक्का ने दो बंकरों में दुश्मन सैनिकों पर अकेले हमला करके कंपनी की जीत सुनिश्चित की और स्वयं बलिदान हो गए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला।



Dainik Jagaran Page No-18

न्यूट्रान तारे में विस्फोट से सबसे चमकीली खगोलीय घटना दर्ज की गई

2004 में आज ही न्यूट्रान तारा मैग्नेटर एसजीआर 1806-20 पर हुए एक विस्फोट से निकलने वाला विकिरण पृथ्वी तक पहुंचा था। यह अब तक दर्ज की गई सबसे चमकीली खगोलीय घटना थी। प्रकाश की इतनी तीव्र चमक थी कि वह चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी के वायुमंडल को रोशन कर गई।



Dainik Jagaran Page No-18

29 देशों ने मिलकर की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना

1945 में आज ही 29 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्स्थिरीकरण के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई।



Dainik Jagaran Page No-18

क्या आप जानते हैं



पहली बार चांद का चक्कर लगाकर लौटे थे एस्ट्रोनाट



27

दिसंबर 1968 को 'अपोलो 8' मिशन छह दिनों की यात्रा के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आया था

- यह इसानों को चांद तक ले जाने वाला दुनिया का पहला मिशन था, जिसने चांद के चारों ओर चक्कर (ऑर्बिट) लगाए थे
- मिशन की शुरुआत 21 दिसंबर को फ्लोरिडा से हुई, जब तीन अंतरिक्ष यानियों (एस्ट्रोनाट) को 'सेटर्न 5' रॉकेट में बैठकर रवाना किया गया
- अंतरिक्ष यानियों ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी की पूरी तस्वीर खींची और चांद की सतह की बेहद करीब से वीडियो फुटेज भेजी
- इस मिशन की सफलता ने साबित किया कि इसान चांद तक जा सकता है और वापस लौट सकता है
- अपोलो 8 की इस सफलता के ठीक एक साल बाद (20 जुलाई) नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था

Hindustan Page No-22

बिहार सहित चार राज्यों में नमूना एकत्र कर रही वन्यजीव संस्थान की टीम

गंगा की सहायक नदियों की स्वच्छता का अध्ययन



विशेष

■ मनीष कुमार भारतीय

गोपालगंज। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल और मिट्टी की स्वच्छता का अध्ययन कराया जा रहा है। इन नदियों की मिट्टी और पानी में प्रदूषण के स्तर की पड़ताल की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि यह जलीय जीव, वनस्पतियों और मानव जीवन के लिए कितना हानिकारक है। इसके लिए देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान की पांच टीमों बिहार सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में मिट्टी और नदियों के जल के नमूने एकत्रित कर रही है।

बिहार में गंडक के अलावा सोन, कोसी, पुनपुन और गंगा में गिरने वाली सभी सहायक नदियों से नमूने एकत्र कर रही है। टीम के दो सदस्यों ने गोपालगंज में गंडक नदी से नमूने लिए हैं। पिछले दो दिनों में बिहार में कार्य कर रही टीम पश्चिमी चंपारण के बगहा, वाल्मीकि नगर तथा गोपालगंज के मंगलपुर और डुमरियाघाट में गंडक नदी से नमूने एकत्र कर चुकी है। टीम आगे रेवाघाट, सोनपुर, सिमरिया घाट सहित अन्य स्थानों से भी नमूने एकत्र करेगी। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की डीन डॉ. रुचि बडोला ने बताया कि आगामी मार्च तक विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए नमूनों की जांच कर रिपोर्ट जारी की जाएगी। इन नमूनों

पानी में प्रदूषण के वास्तविक कारणों की हो रही पड़ताल

गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियां

बिहार

गंडक, कोसी, सोन

झारखंड

दामोदर

उत्तराखंड

भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर

उत्तर प्रदेश

यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, राप्ती

2,525 किलोमीटर में गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक बहती है गंगा



गंगा और उसकी सहायक नदियों से नमूने लेकर जांच की जा रही है ताकि पता चले कि किस तरह के प्रदूषण, भारी धातु व कण हैं जो जलीय जीव व वनस्पतियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

- डॉ. रुचि बडोला, वरिष्ठ वैज्ञानिक व डीन, भारतीय वन्यजीव संस्थान

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कारणों का पता लगाया जा रहा है। नमूनों की जांच से विभिन्न इलाकों में प्रदूषण के वास्तविक कारण सामने आएंगे, जिसके आधार पर जल को स्वच्छ बनाने की कार्ययोजना बनेगी।

- मुकुल राणा, रिसर्व टीम के सदस्य

की जांच के बाद प्रदूषण के स्तर के आधार पर जल की स्वच्छता को लेकर कार्ययोजना बनेगी। इसका उद्देश्य नदियों के जल को निर्मल बनाना है। जांच में नदियों के पानी का पीएच मान,

घुलित ऑक्सीजन, आर्सेनिक, शोशा, पारा, कैडमियम की स्थिति के साथ मिट्टी में मिले रासायनिक तत्वों की मात्रा का आकलन होगा। इसके अलावा राप्ती, सरयू, यमुना, गोमती,

पानी के साथ मिट्टी के भी नमूने लिए जा रहे



गंगा से जुड़ी नदियों के अलग-अलग स्थानों से पानी-मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। इसमें नदियों का

उद्गम स्थल, नदी किनारे बसी आबादी, औद्योगिक क्षेत्र तथा गंगा में मिलने वाले स्थान शामिल हैं, ताकि प्रदूषण के कारणों का पता लगाया जा सके। इसके आधार पर इलाकेवार कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक सर्वे



गोपालगंज पहुंची टीम के सदस्य अजय कुमार के अनुसार गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियों में प्रदूषण का आकलन हो रहा है। इसके लिए बिहार, कोटा (चंबल), वाराणसी, हल्द्वानी और अयोध्या में 15 शोधकर्ता कार्य कर रहे हैं। नदियों को ऊपरी, मध्य और निचले हिस्सों में विभाजित कर नमूने एकत्र किए जा रहे हैं।

अलकनंदा, भागीरथी सहित गंगा से सीधे अथवा अन्य से जुड़ी नदियों से नमूने लिए जा रहे हैं। राजस्थान की चंबल और बनास नदियां यमुना में मिलती हैं और यमुना गंगा में मिलती है।

मोबाइल के उपयोग में राज्य देश में 28वें स्थान पर, आधी आबादी के पास अब भी मोबाइल नहीं

साइबर ठगी के हॉटस्पॉट में बिहार तीसरे स्थान पर

पटना, मुख्य संवाददाता। मोबाइल के उपयोग में बिहार देश में 28वें स्थान पर है। यहाँ की 56.18 फीसदी आबादी मोबाइल का इस्तेमाल करती है। बिहार से अलग हुआ झारखंड भी इस मामले में हमसे आगे है। झारखंड के 64 फीसदी मोबाइल यूजर हैं, जबकि उत्तराखंड तो यह 104 फीसदी है। बिहार भले ही मोबाइल इस्तेमाल के मामले में पीछे है, लेकिन साइबर धोखाधड़ी के हॉटस्पॉट के मामले में देशभर में तीसरे स्थान पर है। इस मामले में हरियाणा पहले तो महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है।

बिहार में नालंदा, पटना, नवादा, शेखपुरा जिले से धोखाधड़ी सबसे ज्यादा हुई है। इन जगहों के तार अन्य राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी जुड़े हैं। साइबर ठगी के जो मामले



अन्य राज्यों में मोबाइल उपयोगकर्ता

राज्य	मोबाइल उपयोगकर्ता
झारखंड	63.95 फीसदी
उत्तर प्रदेश	70.30 फीसदी
उत्तराखंड	106.89 फीसदी
मध्य प्रदेश	69.35 फीसदी
राजस्थान	80.01 फीसदी

बिहार में 56.18% आबादी करती है मोबाइल का इस्तेमाल

बिहार की आधी आबादी के पास अभी भी मोबाइल नहीं है। अभी राज्य में सात करोड़ 38 लाख के पास मोबाइल है। इसमें भी एक करोड़ 71 लाख के पास टूजी सिम है। ये उपयोगकर्ता इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। श्रीजी सिम का इस्तेमाल करने वाले 31 लाख सात हजार 228 हैं।

सामने आए हैं, उनकी जांच में पाया गया कि सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के फोन कॉल इन्हीं जगहों से हुए हैं। दूर संचार विभाग के मुताबिक इस वर्ष 80 लाख के लगभग लोग साइबर

ठगी के शिकार हुए हैं। 90 हजार से ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई हैं। पिछले साल की तुलना में धोखाधड़ी के शिकार होनेवालों की संख्या में 40 फीसदी

1.71 करोड़ लोग अब भी टूजी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं

- साइबर ठगी में हरियाणा पहले तो महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है
- 90 हजार से ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई हैं

66 मोबाइल उपयोगकर्ता अभी बिहार में कम हैं। इस वर्ष दो फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद भी मात्र 56 फीसदी लोग ही मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सात करोड़ 38 लाख लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं।

-दिलीप कुमार, उप महाप्रबंधक, दूरसंचार विभाग

की कमी आई है। 2024 की बात करें तो एक करोड़ 40 लाख लोग साइबर अपराधियों के जाल में फंसे थे, लेकिन संचार साधों के कारण इस बार संख्या कम हुई है।

Hindustan Page N-2

सुखद संयोग पटना समेत अन्य जगहों पर दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी नजर आ रहे, पटना के बीच एनआईटी कैंपस में भी प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया

इस साल ज्यादा दिन रहेंगे प्रवासी पक्षी, शहर से जंगल तक बड़ी मौजूदगी

पटना, मुख्य संवाददाता। इस साल पटना और नालंदा समेत पूरे बिहार में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ज्यादा दिनों तक रहेगी। ठंड जल्द आ जाने से प्रवासी पक्षी हर साल की तुलना में इस वर्ष पहले आ गये। अनुमान है कि ठंड ज्यादा दिनों तक रहेगी। लिहाजा बिहार में प्रवासी पक्षी लंबे समय तक डेरा जमाएंगे।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य अरविंद मिश्रा ने बताया कि इस बार मानसून के बाद की बारिश से जलाशयों में जल की उपलब्धता अधिक होने से प्रवासी पक्षी बिहार में आकर ठहर गए। सहारसा के कोसी नदी के किनारे डुर्गलिन पक्षी दिखाई दिए। यह पक्षी यूरोप की ओर से आते हैं। जबकि



बक्सर में शुक्रवार को गंगा नदी किनारे उड़ता दिखा दुर्लभ प्रवासी पक्षी।

बक्सर गंगा किनारे ग्रे प्लोवर पक्षी दिखाई दी। बिहार में इस बार दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ग्रेटर स्कॉप भी दिखे हैं। फिलहाल ठंड के साथ ही झीलों, नदियों, आर्द्र भूमि से लेकर शहरों के शांत इलाकों तक में परिंदों की

चहचहाहट सुनाई दे रही है। इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक है। राजगीर जू सफारी बना नया ठिकाना: बिहार के प्रमुख पर्यटन केंद्र राजगीर जू सफारी में इस बार प्रवासी

शहर के बीच परिंदों का बसेरा

शहर के बीच भी प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया है। एनआईटी पटना कैंपस में बर्ड वॉचिंग के दौरान कई प्रवासी प्रजातियां देखी गईं। छात्र और शिक्षक सुबह-शाम कैम्पे और दूरबीन के साथ पक्षियों को देखने पहुंच रहे हैं। दानापुर कैट जैसे अपेक्षाकृत शांत इलाकों में भी पेड़ों और जलस्रोतों के आसपास प्रवासी पक्षी नजर आ रहे हैं।

पक्षियों की अच्छी-खासी मौजूदगी देखी जा रही है। जू सफारी के भीतर मौजूद जलाशय और घना हरित क्षेत्र पक्षियों के लिए सुसुधित आश्रय बन गया है। यहां जलपक्षियों जैसे कॉमन सैंडपाइपर, ग्रीन सैंडपाइपर, लिटिल स्टिट, टेनिंग स्टिट

66 इस बार ठंड जल्दी आ गई तो पक्षियों का आगमन भी हुआ है। यह भी एक कारण है कि प्रवासी पक्षियों की संख्या हर जगह दिखाई दे रही है। ठंड लंबी चली तो ये प्रवासी पक्षी ज्यादा दिनों तक यहां रुकेंगे।

-अरविंद मिश्रा, सदस्य, गवर्निंग काउंसिल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी

पर्यावरण के लिए प्रवासी पक्षियों का आना जरूरी

पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा ने बताया कि लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी हमारे जलाशयों व उसके आसपास आते हैं। इनका मुख्य भोजन जलीय वनस्पतियां होती है। अगर ये पक्षी जलीय वनस्पतियां न खाएँ तो ये जलाशय की तल में गाद के रूप में जमा होते जाएंगे।

संख्या बढ़ी है। रेड क्रेस्टेड पोचाई (लालसर), पिन्टेल, कॉमन टेल, शोवेलर, गार्गेनी और विभिन्न प्रजाति के बतख इस मौसम में देखे गए हैं। यद्यो कई हरियाली और आर्द्र भूमि संरक्षण ने इनके प्रवास को आसान बनाया है।

Hindustan Page N-4

बड़े फैसले | वृद्धापेंशन में की गई वृद्धि, रसोइया का मानदेय प्रतिमाह 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपये किया गया

महिला स्वावलंबन की राह और मजबूत हुई



पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चुनावी साल 2025 में कई बड़े फैसले लिए गए। बिहार से शुरू एसआईआर अब पूरे देश में कराया जा रहा है। सात निश्चय-03 के तहत की गई घोषणाओं पर अमल हो जाने के बाद राज्य में उद्योग-धंधों का विकास होगा। युवाओं को घर पर रोजगार मिलने लगेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी ने जहां बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को आर्थिक ताकत दी तो महिला रोजगार योजना ने महिलाओं को स्वावलंबी बनने की आस जगाई है।



06 प्रकार की पेंशन योजनाओं की राशि में 700 की वृद्धि की गई

125 यूनिट तक मुफ्त बिजली ने गरीबों की बचत बढ़ाई है। अपराधियों की संपत्ति-जब्त शुरू होने से अपराध में कमी की उम्मीद भी जगी। सात निश्चय 03 लागू हुआ: सरकार ने राज्य में अगले पांच सालों के लिए सात निश्चय-3 को लागू किया है। राज्य कैबिनेट ने 16 दिसंबर को इसकी स्वीकृति

महिलाओं को रोजगार देने की बड़ी पहल हुई

राज्य में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए कई पहल इस साल सितंबर माह से शुरू हुईं। राज्य सरकार महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए दो लाख रुपये तक की मदद दे रही है। दूसरी ओर इन्हें सुगमता से लोन उपलब्ध कराने के लिए जीविका बैंक की भी शुरुआत कर दी है।

संगठित अपराध और बालू माफिया पर कड़ी चोट

पुलिस ने इस साल बालू, जमीन, शराब और परीक्षा माफिया के संगठित अपराध पर कड़ी चोट की। इसके तहत संगठित अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर अपराध से अर्जित संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गयी। एसओपी बना कर संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी।

एसआईआर से फर्जी वोटर हटे : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व देश में सबसे पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराना शामिल है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद करीब 68 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं।

निजी शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ी परेशानी

भारत आज जब वैश्विक मंचों पर आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व और कूटनीतिक प्रभाव को बात कर रहा है, उसी समय करोड़ों परिवारों के सामने एक साक्षात् चिंता खड़ी है, क्योंकि निजी शिक्षा कितनी महंगी होगी, बेरोजगारी और पढ़ाने कैसे होगा और कैसे कैसे अपनाया जायेगा? निजी शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ी परेशानी

व्यापक तर्क पढ़ाया जा रहा है। भारत में निजी शिक्षा और स्वास्थ्य केवल नीतिगत मुद्दे नहीं, वे जागरूकता के अस्तित्व, परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े जीवन-मरण के प्रश्न बन चुके हैं। अनेक विचारकों ने कहा, सरकारी शिक्षा प्रणाली पर व्यक्ति को जबरन है, भूतू बीमारियों से निपटने के अलावा उनके परिवार पर भी भ्रष्टाचार जमावटी लाती है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चा-चर चर्चा कर रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कितनी भी देश की मानव पूंजी का मूल स्तंभ होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को संवेदन, निर्णय देने और समाज में योगदान करने की क्षमता देती है, जबकि स्वास्थ्य उसे उस क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाता है। यदि हमें से कोई एक भी कमजोर हो, तो विकास को पूरी संरचना

असंगठित हो जाती है। किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सेक्टर नहीं होते, वे जागरूकता के गुरु, अंतरांतर और परिवर्तन की गारंटी होती हैं। भारत में सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली अनेक केवल प्रणाली को मंच नहीं रहे, बल्कि कठिन, निम्न-प्रभाव और यहां तक कि स्थिर आरंभ वाले परिवारों के लिए भी जीवन की प्राथमिक जरूरत बन चुके हैं। एक बच्चा यदि पढ़ नहीं पाता, तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है। भारत में शिक्षा को संविधान ने मौलिक अधिकार माना, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अच्छी शिक्षा अब क्षमता से अधिक खर्च मांग रही है। आज तक औद्योगिक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। यह स्थिति केवल परिवार की बचत नहीं, बल्कि समाज की समानता को भी कमजोर करती है।



अनुलोम-विलोम
शिक्षा-स्वास्थ्य



बदलावों का महत्वपूर्ण वाहक रहा निजी क्षेत्र

भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर व्यापक स्तर का संकेत देता है। निजी शिक्षा नीति (एनपीई) 2020 के तहत, स्टैंडर्ड विद्या के बजाय कोशल विकास, स्थानीय शिक्षा और 2+3+3+4 संरचना (शैल से लेकर माध्यमिक तक) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, अंतर-2024 रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणाम (नैस कक्षा 3 के छात्रों का कक्षा 2 का पाठ न पढ़ पाना) अभी भी चिंता के विषय हैं। शिक्षा के मामले में सरकारत्मक बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक बॉम्ब मीनूट है, जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल, करीब 26 करोड़ छात्र और 1.68 से अधिक शिक्षक/शिक्षालय हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर सुधार कर रहा है, और कुछ रिपोर्टों में इसे 40वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि,

अब भी यहां शिक्षा क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। उच्च शिक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात 24:1 है, जो ऑस्ट्रेलिया के 16:1 के अंतर से कम है। इसके अलावा, आर्थिक सफलता दर अभी भी कम है। निजी शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप, मातृभाषा में शिक्षा, तकनीकी एकीकरण और समाज विकास को बढ़ावा देना है। वहीं देखें, जो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, हालांकि शोध और विश्व स्तर पर शोध में सुधार की आवश्यकता अभी भी है। कुल मिलाकर, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास बहुत बेतरह हुआ है, लेकिन अब गुणवत्ता को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को देखा जाए, तो अभी हाल में ही भारत ने परंपरागत इलाज पर दूसरे वैश्विक समेतन का आयोजन

किया है। देश में डिजिटल स्वास्थ्य समेकन हुआ है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर्तव्य बढ़ा है। इसके साथ ही ई-संजीवनी और टेली-मेटल हेल्थ सेवा जैसे मंच दूर-दूर तक के लोगों को तक पहुंचाया गया है। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य से कई तरह की नई बीमारियों को देखने से उन्मुक्त हो गया है। उसी तरह मस्तिष्क और टीबी जैसे संभावित बीमारियों में काफी कमी दर्ज की गई है। हालांकि, जीवन-शैली में बदलाव से कई तरह की नई बीमारियां भी सामने आई हैं, लेकिन यह उम्मीदें चिंता को बात नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों का उन्मूलन जीवन शैली में सुधार लाकर किया जा सकता है। अतः अधिक धैर्य से ही निजी-वैश्विक-जीवनी में उन्मूलन सुधार किए जाने की जरूरत है।

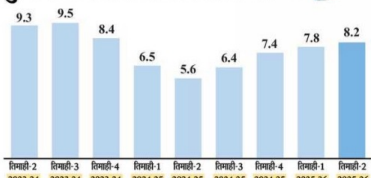
टैरिफ से मुकाबले के लिए भारत 'आत्मनिर्भर' बना

साल 2025 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आसान नहीं था। अमेरिकी टैरिफ, पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की मजबूती ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दबाव में रखा। ऐसे माहौल में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विकास की रफ्तार बनाए रखना और महंगाई को काबू में रखना। इस कसौटी पर देश खरा उतरता दिखा। अमेरिकी द्वारा 50 प्रतिशत का उच्च टैरिफ लगाने के बावजूद भारत की वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रही। महंगाई रिपोर्टें निचले स्तर पर पहुंची और सरकार की नई योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया। कुल मिलाकर यह साल 'आत्मनिर्भर' भारत की ताकत दिखाता है।



ट्रंप के टैरिफ के बावजूद दुनिया में सबसे तेज विकास दर

साल 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक थी। तेज वृद्धि का यह रिकॉर्ड बचाव वित्त वर्ष में भी जारी है और इसकी दो वित्तीय वर्षों में ही जीडीपी ने अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक थी। तेज वृद्धि का यह रिकॉर्ड बचाव वित्त वर्ष में भी जारी है और इसकी दो वित्तीय वर्षों में ही जीडीपी ने अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक थी।



घरेलू मांग से मिला बड़ा सहारा

अमेरिका ने भारत पर अगस्त में 25% टैरिफ लगाया था, जिसे अगस्त में बढ़ाकर 50% कर दिया। इसका असर निर्यात क्षेत्र पर सबसे तेज रहा लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई। यह वृद्धि अत्यंत नहीं आई, इसके पीछे घरेलू मांग में तेजी, जीएसटी में व्यापक सुधार, सेवा क्षेत्र में निरंतर कमाई और पीएसडी का मिश्रण है। इसके अलावा भारत ने अगस्त से अब तक तीन दौर के सब्सिडी कार्यक्रमों पर ध्यान दिया है। इनमें डिजिटल, न्यूजीनिक और ओशन शामिल हैं। वहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईंधन और कच्चा माल 50 देशों से खरीदा जा रहा है।

नई पहल ने इन क्षेत्रों में जान फूँकी

केंद्र ने कई क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू कीं, जो वृद्धि की रीढ़ बनीं। कार्टूट, जीएसटी सुधार और मोडिक नीति से अग्रणी और निर्यात बढ़ा।
■ किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस, निर्यात प्रोत्साहन वृद्धि 4.8% हुई और औद्योगिक उत्पादन सुधारा (आईआईपी) 4% ऊपर गया।
■ शहरी विकास: भारतमाला, सागरमाला और पश्चिमाल जैसी योजनाओं से बुनियादी ढांचा हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े।
■ खनन और खनिज: अफगन से जुड़ी फ्रैक्चरिंग (पिएरएचई) योजना से रोजगार, सड़क और जल संचयन प्रसन्नकरण में निवेश आया। मेगा इंधन योजना से 25 क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा।
■ सेवा क्षेत्र: डिजिटल और विश्व बैंक ने 6.2% की वृद्धि दर्ज की।

महंगाई: आम आदमी को मिला बड़ा सहारा

इस साल महंगाई के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मिली। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक थी। तेज वृद्धि का यह रिकॉर्ड बचाव वित्त वर्ष में भी जारी है और इसकी दो वित्तीय वर्षों में ही जीडीपी ने अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 6.5% रही, जो दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक थी।

मासिक किस्त घटी

- खुदरा महंगाई में नरमी के बाद आरबीआई ने फरवरी से अब तक दोहरा दर में 1.15% की कटौती की
- इससे अवास ऋण को फ्लोडिंग ब्याज दरें 8.75 से घटकर 7.50 फीसदी तक आईं गईं हैं

सोना-चांदी: निवेशकों के मनोसे और कमाई में अचल

2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों को सबसे ज्यादा लाभ दिया। चांदी ने करीब 140 फीसदी तो सोने ने 78% से अधिक का रिटर्न दिया। पिछले साल की तुलना में यह दोड़ना से भी अधिक मुनाफा है। चांदी ने साल 2024 में 38% तक और सोने ने करीब 25 फीसदी तक रिटर्न दिया था। इस साल सोने के दाम 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के मानकीकृत रूप तक बढ़े। चांदी के दाम 2,14,500 रुपये प्रति किलोग्राम का नया रिकॉर्ड छुड़ा। अगस्त में इसका भाव 89,900 रुपये था। खनन उत्पादन में निर्यात और औद्योगिक मांग ने सोने की कीमतों को खींचा है कि अगर टैरिफ घटे तो बाजार को अग्रणी और चांदी के दाम 2,50 लाख का स्तर छू सकते हैं। वहीं, यूरोपियन निवेश की मांग बढ़ने से सोने के दाम अगले साल 1,60 लाख तक बढ़ सकते हैं।

इन मोर्चों पर भी सफलता

जीएसटी संग्रह

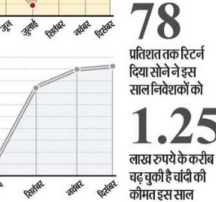
वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह 13 बिलियन डॉलर बढ़ा। अगस्त में जीएसटी संग्रह 13 बिलियन डॉलर बढ़ा। अगस्त में जीएसटी संग्रह 13 बिलियन डॉलर बढ़ा।

सूचीआई

सूचीआई ने रिपोर्ट प्रदर्शन किया। पूरे साल कुल लेनदेन की मात्रा लगभग 230 अरब रही, जबकि मूल्य 299 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। अगस्त में भी 20.47 अरब लेनदेन हुए, जबकि मूल्य 26.32 लाख करोड़ रुपये रहे।

विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर भी इस साल मजबूती का पैमाना रहा। 2025 में विदेशी मुद्रा भंडार का रिपोर्ट डबल कर 692.58 अरब डॉलर रहा, जो 21 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया। हालांकि, सर्वोच्च रिपोर्ट 704.89 अरब डॉलर है, जो दिसंबर 2024 में बना था। दिसंबर 2025 में भंडार 688.95 अरब डॉलर के आसपास रहा।



भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों के बीच तलाशने होंगे विकास के अवसर

आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर उभरेगा। विकास के लिए देश में मांग बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास पर ध्यान देना होगा। ऐसे में कृषि और अग्रणी क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र पर 46 प्रतिशत लोगों को निर्यात है। इस क्षेत्र में विकास के लिए देश में मांग बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास पर ध्यान देना होगा। ऐसे में कृषि और अग्रणी क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र पर 46 प्रतिशत लोगों को निर्यात है। इस क्षेत्र में विकास के लिए देश में मांग बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास पर ध्यान देना होगा।

उम्मीदें@2026

- 1 रुपये में पेंसिलरिफ निर्यात: इस साल रुपये में रिपोर्ट निर्यात 91 रुपये के स्तर पर बढ़ा गया।
- 2 अमेरिका से करार अटक: अमेरिका से डिजिटल व्यापार समझौता अभी अवर में है। कई दौर की वार्ताओं से जुड़ी है लेकिन मुझे पर सफलता से बने फल के कारण करार अटक है। माना जा रहा है कि समझौते के पहले वार्ता को लागू करने के लिए दोनों देश फेरफाल से लगे हैं।
- 3 बढ़त व्यापार घाटा: व्यापार घाटा 2025 में रिपोर्ट स्तर पर बढ़ा, जो अर्थव्यवस्था के लिए नए जोखिम पैदा कर रहा है। अक्टूबर में भारत का निर्यात 1.18 बिलियन डॉलर बढ़कर 41.68 अरब डॉलर के रिपोर्ट स्तर पर पहुंच गया।

वेदना से चेतना तक

रामानुज पाठक

म

नुष्य का जीवन केवल घटनाओं की शृंखला नहीं है, बल्कि अनुभूतियों की एक सतत् और गहन यात्रा है। इस यात्रा में सुख जितना क्षणिक होता है, वेदना उतनी ही गहरी और स्थायी अनुभूति के रूप में सामने आती है। संघर्ष, असफलता, हानि और अपूर्णता— ये सभी जीवन को केवल चुनौती नहीं देते, बल्कि उसके अर्थ पर प्रश्न भी खड़े करते हैं। प्रत्येक अनुभव अपने भीतर वेदना का बीज लिए होता है, लेकिन यह वेदना स्वयं में लक्ष्य नहीं है। उसका वास्तविक मूल्य तभी प्रकट होता है, जब वह चेतना में रूपांतरित हो जाती है।

चेतना वह दृष्टि है, जो वेदना को केवल सहने योग्य नहीं, बल्कि समझने योग्य बनाती है। बिना चेतना के वेदना अंधकार है— दिशाहीन, बोझिल और अर्थहीन। मगर चेतना के स्पर्श से वही वेदना आत्मबोध, विवेक और जीवनदर्शन का स्रोत बन जाती है। इतिहास, दर्शन और मानव अनुभव बार-बार इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि केवल पीड़ा से महानता नहीं जन्म लेती, बल्कि पीड़ा को समझने की क्षमता से मनुष्य ऊंचा उठता है। इसी गहन सत्य की अभिव्यक्ति है यह कथन— 'वेदना बगैर चेतना दुर्लभ है।'

दार्शनिक दृष्टि से वेदना केवल पीड़ा नहीं, बल्कि जीवन की गूंज है। वह हमारे भीतर प्रश्न, जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण को जन्म देती है। चेतना ही वह माध्यम है, जो वेदना को साधारण अनुभव से ऊपर उठाकर व्यक्तित्व, विवेक और जीवन दर्शन में रूपांतरित करती है। महात्मा बुद्ध ने जीवन की सार्वभौमिक पीड़ा— जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था— का साक्षात्कार कर उसे करुणा और आत्म-ज्ञान की चेतना में बदला। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने चित्त-वृत्तियों के संघर्ष को योगदर्शन में रूपांतरित किया और आदिकवि वाल्मीकि ने अपने जीवन की हिंसा और अवमानना को करुणा तथा काव्य की चेतना में ढाल दिया।

इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां पराजय, अपमान और कष्ट केवल दुख बनकर नहीं रुके, बल्कि चेतना का स्रोत बने। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने मृत्यु-दंड को भी सत्य और विवेक की साधना में बदल दिया। कबीर ने सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा को आत्मबोध तथा निर्भीक वैचारिक चेतना का माध्यम बनाया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि चेतना वेदना से पलायन नहीं सिखाती, बल्कि उसे समझकर पार करने की शक्ति देती है।

जीवन में प्रत्येक चुनौती, असफलता और कठिनाई वेदना का अनुभव कराती है— चाहे वह शारीरिक चोट हो, मानसिक संताप, सामाजिक असमानता या आर्थिक हानि। अगर इन अनुभवों को केवल दुख या शिकायत के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो

वे निरर्थक बोझ बन जाते हैं, लेकिन जब वही अनुभव आत्मचिंतन का कारण बनते हैं, तब वे हमारे दृष्टिकोण, निर्णय और आचरण को परिष्कृत करते हैं। यही वह क्षण होता है, जब वेदना चेतना में रूपांतरित होती है।

चेतना केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती, वह सामाजिक और नैतिक दायित्व का रूप भी ग्रहण करती है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने अपने सामूहिक दुख को समझा और उसका विवेकपूर्ण विश्लेषण किया, उन्होंने परिवर्तन और पुनर्निर्माण का मार्ग चुना। इसके विपरीत, जहां पीड़ा केवल क्रोध, प्रतिशोध या पलायन में बदल गई, वहां विनाश और विघटन ही परिणाम बना। इस प्रकार चेतना, वेदना को सृजनात्मक शक्ति में रूपांतरित कर देती है।

आखिर में यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदना से मुक्त जीवन की कल्पना अवास्तविक है, लेकिन चेतना-विहीन जीवन निश्चय ही अर्थहीन है। वेदना मनुष्य को तोड़ भी सकती है और गढ़ भी सकती है— यह अंतर केवल चेतना का है। इतिहास के महान व्यक्तित्व, दार्शनिक चिंतक और सामाजिक परिवर्तनकर्ता इसलिए स्मरणीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को पलायन या प्रतिशोध में नहीं, बल्कि आत्मबोध, उत्तरदायित्व और करुणा में बदला।

वेदना जब केवल सहने की जाती है, तो वह बोझ बनती है, जब समझी जाती है, तो वही चेतना बन जाती है।

यही चेतना मनुष्य को उसके निजी दुख से ऊपर उठाकर सामाजिक संवेदना, नैतिक दृष्टि और मानवीय करुणा से जोड़ती है। बिना चेतना के अनुभव केवल स्मृतियां होते हैं, लेकिन चेतना से युक्त अनुभव इतिहास बन जाते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि वेदना जीवन की अपरिहार्यता है, पर चेतना उसका उत्कर्ष। चेतना ही वह दीपक है, जो वेदना के अंधकार में अर्थ, दिशा और आशा का प्रकाश भरता है। जब तक मनुष्य वेदना को समझने का साहस नहीं करता, तब तक वह केवल पीड़ित रहता है, लेकिन जिस क्षण वह उसे चेतना में रूपांतरित कर लेता है, उसी क्षण वह सचेत, जाग्रत और पूर्ण मनुष्य बन जाता है।

यही कारण है कि वेदना बगैर चेतना, न केवल दुर्लभ है, बल्कि मानवीय गरिमा और विकास की कसौटी भी है। इस दृष्टि से देखा जाए, तो आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौती वेदना की अधिकता नहीं, बल्कि चेतना की न्यूनता है। सूचना, गति और उपलब्धियों से भरे इस युग में मनुष्य अनुभव तो बहुत करता है, पर उन्हें आत्मसात करने का अवकाश खोता जा रहा है। परिणामस्वरूप वेदना संचित होती जाती है, लेकिन चेतना में रूपांतरित नहीं हो पाती। ऐसे में आवश्यक है कि व्यक्ति ठहरकर देखे, अनुभवों पर विचार करे और उनसे संवाद स्थापित करे। यही ठहराव, यही आत्मसंवाद वेदना को चेतना में बदलने की प्रक्रिया है, जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं, बल्कि जाग्रत बनाती है।

दुनिया मेरे आगे

इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां पराजय, अपमान और कष्ट केवल दुख बनकर नहीं रुके, बल्कि चेतना का स्रोत बने। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने मृत्यु-दंड को भी सत्य और विवेक की साधना में बदल दिया। कबीर ने सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा को आत्मबोध तथा निर्भीक वैचारिक चेतना का माध्यम बनाया।

ऊर्जा की जरूरतों का हरित विकल्प

हरित हाइड्रोजन में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपार क्षमता है। यह परिवहन और उद्योग में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो ऊर्जा का एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत होगा।

अखिलेश आर्यदु

कें

द्र सरकार ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य है, हर वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। गौरतलब है हरित हाइड्रोजन उद्योग जिस तरह बढ़े पैमाने पर स्थापित हो रहे हैं, ऐसे में उच्च क्षमता वाला बिजली उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए जो विधि उपयोग में लाई जा रही है, वह सुगम और सस्ती है। मगर वहीं पर हाइड्रोजन ऊर्जा की आपूर्ति के आंकड़े वर्तमान में सीमित हैं, क्योंकि दुनिया में करीबन 96 फीसद हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से पैदा होती है। इसमें महज तकरीबन चार फीसद बिजली के इलेक्ट्रोलीसिस (विद्युत अपघटन) द्वारा तैयार की जाती है। भारत सरकार चाहती है कि जब तक हर गांव और बाजार-मुहल्ले की ऊर्जा जरूरतें इसके जरिए न पूरी हों, तब तक इसके लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इससे जागरूकता आएगी और लोग हाइड्रोजन ईंधन की महत्ता को भी समझने लगेंगे।

हाइड्रोजन आने वाले चक्र का ऊर्जा आपूर्ति का आधार बनेगा। हरित हाइड्रोजन में कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की अपार क्षमता है। यह परिवहन और उद्योग में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो ऊर्जा का एक निरंतर और विश्वसनीय स्रोत होगा। कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन में कमी लाने वाला ऊर्जा विकल्प का सबसे बेहतर स्रोत हरित हाइड्रोजन बनने जा रहा है। आने वाले समय में शायद हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होगा। जिंदगी को अधिक सुगम बनाने के लिए इसका उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग को जिंदगी को प्रभावित करेगा।

उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्य स्वच्छ किफायती और टिकाऊ ऊर्जा के लिए बड़े सोलर पार्क, हरित हाइड्रोजन, विकेंद्रीकृत ऊर्जा, और माइक्रो ग्रिड के जरिए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर खास जोर दे रहे हैं। राज्य सरकार ने 2047 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिल कर आगे की कार्ययोजना तैयार की है। इसी तरह की योजना देश के सभी राज्यों को तैयार करनी होगी, क्योंकि कार्बन-मुक्त ऊर्जा पैदा करने के लिए जैव ऊर्जा सबसे किफायती है। इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हरित हाइड्रोजन में कई संभावनाएं छिपी हैं।

दरअसल, ऊर्जा क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए सरकार हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वैश्विक क्षमताओं के बीच भारत को अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के मिशन के माध्यम से 2030 तक 50 लाख टन (एमएमटी) वार्षिक हरित हरित हाइड्रोजन क्षमता हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2030 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लागू करने के लिए 19,744 करोड़ का परिव्यय मंजूर कर चुकी है। इससे देशभर में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।



हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया कि भारत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने 2030 तक हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता जोड़ने की वार्षिक

दु

नियामक में परिवहन, पतन और स्टील सहित कई क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में हाइड्रोजन का बड़ा भंडार है, जिसे 200 वर्ष से ज्यादा समय तक जर्खी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल नए आविष्कारों के जरिए घरेलू इस्तेमाल के लिए जल्द ही सुलभ हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की वार्षिक आवश्यकता के बारे में बताया गया कि भारत बिजली खरीद या बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए पहले से ही तैयार 40 गीगावाट क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उत्पादन क्षमता 50 लाख टन रखी है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि ऊर्जा की कमी जिन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, उन सभी क्षेत्रों में इसका

इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य की घोषणा की है। इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका उत्पादन कई नजरिए से खास है। पर्यावरणीय मानकों पर यह सबसे खरा उतरता है, क्योंकि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, इलेक्ट्रोलीसिस द्वारा किया जाता है, जो प्रक्रिया में सौर, पवन या जलविद्युत जैसे अक्षय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल कर पानी को आवसनीय और हाइड्रोजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्वच्छ और उत्सर्जन-मुक्त ईंधन प्राप्त होता है। इसमें जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपार क्षमता है।

दुनियाभर में परिवहन, पतन और स्टील सहित कई क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में हाइड्रोजन का अकूत भंडार है, जिसे दो सौ वर्ष से ज्यादा समय के लिए जरूरी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल नए आविष्कारों के जरिए घरेलू उपयोग के लिए जल्द ही सुलभ हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की वार्षिक आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि भारत बिजली खरीद या बिक्री समझौतों पर हस्ताक्षर के लिए पहले से ही तैयार 40 गीगावाट क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भी बताया गया है कि वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 160 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। भारत को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़नी होगी।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की शुरुआती परियोजनाओं के लिए नए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसमें सौर कोरड रूप के परिव्यय के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जैविक पदार्थ का उपयोग शामिल है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जैविक पदार्थों के उपयोग सहित अत्याधुनिक तकनीक को जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए कुल सौ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो एनजीएचएम के तहत नवउद्यम योजनाओं के लिए पहले से आवंटित सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। गौरतलब है एनजीएचएम का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। साथ ही इसका लक्ष्य 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और छह लाख से अधिक हरित रोजगार उत्पन्न करना भी है। रोजगारपरक होने की वजह से इस क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है।

ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हाइड्रोजन सहित सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटी है, इनसे आने वाले चक्र में कई क्षेत्र में ऊर्जा की कमी से कार्यों में आने वाली रुकावटों से निजात मिलेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने में दिखाई देगा। देश के बड़े शहरों, नगरों और कस्बों में कार्बन और धूल प्रदूषण से बीमारियों सहित होने वाली तमाम परेशानियों से लोग बचेंगे। इससे अरबों रुपए बचेंगे। साथ ही साथ हथ्ठी, मरिात्क, रक्त, आंत, आंख और सांस आदि से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों में कमी आएगी और औसत उम्र में वृद्धि भी होगी।

आवश्यक हुआ एआइ को अपनाना

अगर 2024 वह साल था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) ने बोलना सीखा तो 2025 वह साल रहा, जब एआइ के हाथ बढ़े और उसका दायरा एवं प्रभाव बढ़ा। यह वह वर्ष रहा, जब एआइ निर्णायक रूप से डेमो और पायलट प्रोजेक्ट्स से आगे निकलकर वास्तविक क्रियान्वयन, स्वायत्तता और बड़े पैमाने पर उपयोग में उतरा। चर्चा एआइ टूल्स के इस्तेमाल से आगे बढ़कर एआइ एजेंट्स के निर्माण पर आ गई। जेनरेटिव एआइ को जगह एजेंटिक एआइ प्रमुख अवधारणा बन गई। एजेंटिक एआइ ऐसे सिस्टम को कहते हैं, जो सिर्फ इंसाओं को सलाह नहीं देते, बल्कि एंटरप्राइज साफ्टवेयर के भीतर बहु-चरणीय वर्कफ्लो को स्वयं अंजाम देते हैं। एजेंटिक ब्राउजरस से लेकर आटोनामस कामर्स और वर्कफ्लो आटोमेशन तक, एआइ एक सहायक से बढ़कर जूनियर सहयोगी की तरह व्यवहार करने लगा। वर्ष 2025 आत्ममंथन का भी साल रहा। कंपनियों ने दिखावटी प्रयोगों को छोड़कर ठोस और मापने योग्य रिटर्न आन इन्वेस्टमेंट की मांग शुरू की। एआइ को अपनाना अब अपवाद नहीं, बल्कि जरूरत बन गया। कोडिंग पहला ऐसा उपयोग क्षेत्र बना, जहाँ एआइ का व्यापक पैमाने पर असर दिखा। क्लाउड, कर्सर और कोपायलट जैसे एआइ टूल्स एंटरप्राइज स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नया कोड तैयार करने लगे। इसके साथ ही साफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका भी बदलने लगी। अब वह सिर्फ कोड लिखने वाला नहीं, बल्कि मशीन श्रम का पर्यवेक्षक और सिस्टम आर्किटेक्ट बनना जा रहा है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग के शब्दों में कहें तो हम साफ्टवेयर एजेंट्स के लिए एचआर मैनेजर बन गए हैं। इस गुजरते साल परदे के पीछे एआइ की भौतिक नींव भी तैयार हो रही थी। एटम्स फार एल्गोरिदमस आंदोलन के तहत बड़ी टेक कंपनियों ने गीगावाट-स्तरीय डाटा केंद्रों को ऊर्जा देने के लिए परमाणु ऊर्जा की ओर रुख किया। एआइ ने सिर्फ साफ्टवेयर को नहीं बदला, बल्कि वैश्विक ऊर्जा अवसंरचना को भी नए सिरे से आकार देना शुरू कर दिया। इसी बीच चीन ने



जसप्रीत बिह

आने वाला साल हमें यह तय करने पर मजबूर करेगा कि हम एआइ के साथ कैसे जाएं, काम करें और शासन करें

सहयोगी का रूप लेती एआइ तकनीक • प्रतीकात्मक

बिना शोर-शराबे के वर्ष 2025 में बढ़त बन ली। उसका फोकस एजीआइ (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) की समय-सीमाओं की घोषणा करने के बजाय अनुप्रयोगों, ओपन-सोर्स नेतृत्व और ऊर्जा प्रचुरता पर रहा। एजीआइ को मानव-स्तरीय एआइ भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो लगभग सभी संज्ञानात्मक कार्यों में मानव क्षमताओं के बराबर या उनसे भी आगे निकल सकती है। ओपन-सोर्स का स्वामित्व एक बार फिर दीर्घकालिक रणनीतिक बढ़त साबित हुआ। बीत रहा वर्ष एआइ के स्याह पहलुओं को भी उजागर कर गया। हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। डीपफेक्स ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए खतरा पैदा किया, एआइ कंपैनियंस ने अकेलेपन और मानवीय संबंधों को लेकर असहज सवाल खड़े किए और उद्योग एक डाटा सीमा से टकरा गया, जिससे सिंथेटिक डाटा की ओर झुकाव बढ़ा। इसके बावजूद इस साल के अंत तक गूगल एक अप्रत्याशित एआइ लौडर के रूप में उभरा, जिसने चिप्स, माडल्स, डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी फुल-स्टैक ताकत का लाभ उठाया।

अगर वर्ष 2025 क्षमताओं का साल था तो 2026 विवेक का होगा। हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे रीजनिंग वेब का युग कहा जाता है, जहाँ सर्च इंजन लिंक दिखाने के बजाय सीधे उत्तर देने वाले इंजन बन जाएंगे और एआइ ब्राउजर ज्ञान को समेटकर प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इससे वेब की आर्थिक संरचना को नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा, अन्यथा यह उन्हीं क्रिप्टर्स को नुकसान पहुंचाएगा, जिन पर एआइ निर्भर है। इसी समय एजेंट्स कोपायलट से आगे बढ़कर सहयोगी बन जाएंगे और हल्की मानवीय निगरानी में पूरे वर्कफ्लो चला सकेंगे। वर्ष 2026 वह साल भी होगा, जब एआइ को शरीर मिलेगा। फिजिकल एआइ यानी रोबोट्स और आटोनामस सिस्टम्स प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर वेयरहाउस, फैक्ट्रियों और शहरों की सड़कों तक पहुंचेंगे। सेल्फ-ड्राइविंग कारों का अलग-अलग शहरों और महाद्वीपों में विस्तार इस बात का संकेत है कि एंबेडेड इंटेलिजेंस अब कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक संचालन बन चुकी है। सेल्फ-ड्राइविंग कारें इंसानी हस्तक्षेप के बिना चल सकती हैं। अगले साल एआइ वैल्यूएशंस में सुधार जरूर आएगा, लेकिन गिरावट नहीं, क्योंकि तकनीक ठोस है, इन्फ्रास्ट्रक्चर गहरा है और कैश फ्लो मजबूत है। इसके बजाय जो चीज सबसे मूल्यवान बनेगी, वह है मानवीय तत्व। जब एआइ-जेनरेटेड कंटेंट इंटरनेट पर बाढ़ की तरह फैल जाएगा, तब सत्यापित मानवीय रचनात्मकता, विवेक और जुड़ाव एक तरह की लकजरी बन जाएंगे। कुल मिलाकर दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए भी 2026 एआइ के क्षेत्र में एक निर्णायक क्षण लेकर आएगा। संप्रभु एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट का विस्फोट और जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) तक पहुंच अब वास्तविक लगने लगी है। अगर 2025 ने हमें दिखाया कि एआइ क्या कर सकता है तो 2026 हमें यह तय करने पर मजबूर करेगा कि हम उसके साथ कैसे जाएं, काम करें और शासन करें। कच्ची बुद्धिमत्ता का युग पीछे छूट चुका है। अब विवेक का युग शुरू हो रहा है।

(लेखक एआइ एंड बियांड के को-फाउंडर हैं)

response@jagran.com

सांस्कृतिक एकता का सूत्र



सीपी राधाकृष्णन

काशी-तमिल संगम अतीत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान की जीवंत सन्तान और भविष्य के विकसित भारत संकल्प को एक सूत्र में पिरोते हैं

भारत के सनातन सांस्कृतिक आत्मा को यदि किसी एक पवित्र मंत्र पर सजीव रूप में देखा जा सकता है, तो वह है काशी-तमिल संगम। यह एक ऐसा अमूर्त उत्सव है, जहाँ उत्तर और दक्षिण की संस्कृति, सभ्यताएं, भाषाएं और परंपराएं एक विराट भारतीय परिवार की तरह एक-दूसरे का आलिंगन करती हैं। संगम के चौथे संस्करण के अवसर पर मैंने गहराई से यह अनुभव किया कि काशी और तमिलनाडु का यह संबंध केवल भौगोलिक या ऐतिहासिक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से बहती आध्यात्मिक सांस्कृतिक धारा का अविस्तर प्रवाह है। काशी अविनाश है, अनादि काल से है। काशी को प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की राजधानी कहा जाता है। दूसरी ओर तमिलनाडु, जिसकी भाषा विश्व की प्राचीनतम जीवित भाषाओं में से एक है, भारत की सनातन परंपरा, साहित्य, संगीत और दर्शन का महान वाहक रहा है। काशी-तमिल संगम

इन दोनों सभ्यतागत स्तंभों के बीच के सेतु को पुनः सुदृढ़ करता है। उत्तर और दक्षिण के बीच यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कोई नया प्रसंग नहीं है। देवार्म नालवर के भक्ति गीतों से लेकर काशी में गूंजते संत कबीर के भजनों तक साधना की भाषा एक ही रही है। वह है भक्ति, ज्ञान, मानवता की भाषा।

काशी में तमिल सेतों की उपस्थिति और दक्षिण भारत में काशी को 'मोक्ष की नगरी' के रूप में मान्यता, इस गहरे संबंध को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृढ़ संकल्प से 2022 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। आज यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। यहां गंगा की संस्कृति और कावेरी की परंपराएं एक-दूसरे से मिलकर भारत की सांस्कृतिक अखंडता को आगे बढ़ाती हैं। प्रधानमंत्री ने हाल में 'मन की बात' में इस उत्सव का उल्लेख करते हुए कहा था कि 'यह संगम विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक काशी और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक तमिल का संगम है।' उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति को भारत का गौरव बताते हुए सभी से तमिल संखने का आग्रह भी किया। यह आग्रह भारत की भाषाई विविधता को अपनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

काशी-तमिल संगम के प्रत्येक संस्करण में तमिलनाडु के छात्र, अध्यापक, लेखक, मीडिया प्रोफेशनल्स, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लोग, महिलाएं और आध्यात्मिक विद्वान काशी आते रहे हैं। इस दौरान वे काशी के मंदिरों, तमिल से संबंधित केंद्रों और



अपेक्ष राजगुरु

अयोध्या एवं प्रयागराज जैसे नगरों से परिचित होते हैं। चौथे संस्करण ने संगम की सीमा और महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। काशी-तमिल संगम 4.0 में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का उद्देश्य भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की चेतना को और गहराई देना है। संगम के दौरान उत्तर प्रदेश के 300 विद्यार्थी तमिलनाडु पहुंचे हैं और विभिन्न संस्थानों में तमिल भाषा सीख रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु की समृद्ध परंपराओं, त्योहारों और भारतीय परंपरा की एकता से भी परिचित कराया जाएगा। तमिलनाडु से भी 50 तमिल शिक्षक वाराणसी पहुंचे हैं और संगम के दौरान 1,500 से अधिक छात्रों को तमिल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमिल की मधुर ध्वनि काशी में गूंजी, इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है?

काशी-तमिल संगम 4.0 को एक और विशिष्ट और प्रेरक पहल 'अगस्त्य अभियान' है। यह अभियान तमिलनाडु के तेनकाशी से काशी तक एक प्राचीन

सभ्यतागत मार्ग को पुनर्स्थापित करता है। महर्षि अगस्त्य भारतीय सभ्यता के उन महान ऋषियों में से हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक संवाद को सुदृढ़ किया। उन्हें तमिल भाषा और सिद्ध चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है। वे तमिल संस्कृति को उत्तर भारत तक ले कर आए। अगस्त्य अभियान उनके उसी योगदान को स्मरण करते हुए उत्तर-दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को पुनः रेखांकित करता है।

काशी-तमिल संगम 4.0 यह संकेत देता है कि भारत अपनी प्राचीन सभ्यतागत जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। यह आयोजन हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अतीत की स्मृतियां केवल विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाली प्रेरणा होती हैं। ऐसे मंचों के माध्यम से सांस्कृतिक संवाद, आंतरिक एकता और राष्ट्रीय चेतना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। संगम अतीत की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान की जीवंत सहभागिता और भविष्य के विकसित भारत जैसे

राष्ट्रीय संकल्प, तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत का विकास केवल आर्थिक या तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत चेतना में निहित हैं। काशी तमिल संगम 4.0 ने यह स्पष्ट किया कि भारत सरकार सांस्कृतिक एकीकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस आयोजन ने विभिन्न समुदायों को जोड़ है। इसने यह पुनः स्थापित किया है कि भारत की सभ्यतागत शक्ति उसकी विविधता की एकता में निहित है। आज जब विश्व विविधताओं के बीच तनाव और संघर्षों से जुझ रहा है, तब भारत का विविधता को उत्सव के रूप में स्वीकार करना वैश्विक संदर्भ में भी प्रेरणास्पद बनकर उभरता है।

महाकवि सुब्रमण्य भारतीय ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहाँ सिंधु तट पर तेलुगु गीत गाए जाएं और कावेरी की धरती के बच्चे गंगा के तट पर उत्सव मनाएं। उस स्वप्न ने काशी-तमिल संगम के माध्यम से आज मूर्त रूप ले लिया है। इस संगम से प्रेरणा लेकर हम कह सकते हैं: 'कावेरी की पुत्री, गंगा के तट पर गाती है, भक्ति की मधुर धारा में, अपनी धुन मिलाती है। गंगा का पुत्र भी, कावेरी के तट पर आता है, तमिल के मंठे स्वरो में, भारत का नद सुनाता है।' काशी से शुरू हुआ यह कार्यक्रम, तमिल आध्यात्मिक विरासत की सबसे पवित्र जगहों में से एक रामेश्वरम में खत्म होगा। यही वह सेतु है, जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है और भारत को एक परिवार होने की अनुभूति कराता है।

(लेखक उपरोक्त हैं।
response@ajgrn.com)

टैरिफ से तनाव के बावजूद बढ़ा भारत



अरुण कुमार | वरिष्ठ अर्थशास्त्री

सिंहवलोकन- 2025

इ

स वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। इसका बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ रहा। इसकी वजह से भारत के निर्यात, भूगतान संतुलन, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

दरअसल, ट्रंप ने नवंबर 2024 में अमेरिकी चुनाव जीता और तभी से यह आशंका थी कि वह अमेरिकी-हितैषी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भारत व चीन पर अमेरिकी कामगारों की अच्छी नौकरियाँ खीनने का आरोप लगाया और उनको वापस लाने का वादा भी किया। यह संकेत था कि दूसरे देशों में अमेरिकी निवेश घटेगा। उनके सत्ता संभालने के बाद कर्मोवेश ऐसा ही हुआ।

भारत में साल 2024 में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के बावजूद निजी निवेश कमजोर था, जिसका असर विकास और रोजगार-सृजन पर पड़ रहा था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कई वर्षों से 70 से 75 फीसदी क्षमता का ही उपयोग हो रहा था, जो अर्थव्यवस्था में कमजोर मांग का संकेत था।

इस पृष्ठभूमि में यदि हम इस वर्ष का विश्लेषण करें, तो 10 वृद्धि घटानाएं नजर आती हैं। पहली- 1 फरवरी, 2025 को पेश किया गया केंद्रीय बजट, जिसमें मांग को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। उम्मीद थी कि इससे मध्यम वर्ग के हाथों में खर्च करने लायक पैसे होंगे और वे अपना उपभोग बढ़ाएंगे। मगर इसमें असंगठित क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया गया। हालांकि, बजट ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह संकेत भी दिया कि भारत प्रमुख अमेरिकी निर्यातों पर सीमा शुल्क कम करके अमेरिका के साथ अपना ट्रेड-सुरक्षात्मक करेगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति से डिगे नहीं और

अमेरिकी नीति के कारण भारत के निर्यात, रुपये की कीमत, निवेश आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पेश है बीतते साल में अर्थव्यवस्था के खास दस पहलू :



13 फरवरी को उन्होंने व्यापारिक साझेदारी वाले देशों से आयात पर व्यापक पारस्परिक सीमा शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत को उम्मीद थी कि रणनीतिक साझेदार होने के नाते उसके साथ अनुकूल व्यवहार किया जाएगा। मगर जब 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा की गई, तो भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क का एलान किया गया। हालांकि, इसे जुलाई तक स्थगित रखा गया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप 90 दिनों में 90 देशों के साथ 90 समझौते करना चाहते थे। जुलाई में, व्यापार समझौते पर सहमति न बनने पर टैरिफ लगाने की समझ-सौमा बढ़ाकर 1 अगस्त की गई, पर 7 अगस्त को ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। यह साल की दूसरी बड़ी आर्थिक घटना थी।

तीसरी महत्वपूर्ण घटना इसी से जुड़ी है, जो है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कई वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का एलान करना। इसका उद्देश्य कीमतों को कम करना और खपत को बढ़ावा देना था, ताकि अमेरिका द्वारा लगाए गए

दंडात्मक टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव से अंतर किए जा सके। हालांकि, इससे सितंबर में विक्री में ठहराव आया, लेकिन जीएसटी दरों में कमी होने से यह तेजी से बढ़ी, खासकर लक्जरी उत्पादों की विक्री में।

चौथी घटना पहली और दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों की घोषणा रही। इन आंकड़ों से आर्थिक वृद्धि में तेज उछाल दिखाई दिया। आईएमएफ का हवाला देते हुए यह दावा भी किया गया कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मगर बाद में पता चला कि यह एक अनुमान था, जो साल के अंत तक के लिए लगाया गया था और कई कारकों पर निर्भर था (जैसे- महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत आदि)।

पांचवीं घटना रही, भारत के जीडीपी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर आईएमएफ द्वारा संदेह जताना। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से प्राप्त आंकड़े व जीडीपी में भारी अंतर को लेकर उसकी शंकाएं थीं। इसका असर विदेशी निवेशकों पर पड़ा और उन्होंने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया। विदेशी संस्थायत निवेशक

भारत से पैसा निकालकर अब अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, जहां प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में तेजी के कारण शेयर बाजार में उछाल आया है।

रुपये का गिरना छठी घटना है। डॉलर के मुकाबले यह रिकॉर्ड 91 के पार चला गया। टैरिफ और सोने के आयात के कारण चालू खाता घाटा बढ़ गया है। हालांकि, पहले पूंजी खाता इसे सहायता देता था, लेकिन अब यह भी ऋणात्मक हो गया है।

आठवें वैतन आयोग की स्थापना का एलान सातवीं अहम घटना थी। इस आयोग के नियम पिछले आयोगों से अलग हैं। ऐसा केंद्र व राज्यों की कमजोर आर्थिक दशा के कारण हो रहा है। इस स्थिति को मैं आठवीं महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ। वित्त आयोग ने पिछले महिने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जो राजकोषीय संघवाद को प्रभावित कर सकती है, खासतौर से इसलिए, क्योंकि 'फ्रीबीज' पर अधिक जोर देने के कारण कई राज्य सरकारों की आर्थिक सेहत खराब है।

नौवीं घटना है- परमाणु दायित्व से संबंधित शांति विधेयक का पारित होना। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। इससे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में तेजी आएगी और जीवाणु ईंधन का उपयोग घटेगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विधेयक को संसदीय समिति के पास विचार-विमर्श के लिए भेजने की मंजूरी भी दी गई है। इससे भारत में उच्च शिक्षा को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। इसकी सफलता भारतीय अनुसंधान और विकास को गति देगी, जिसमें हम अन्य देशों से पिछड़ रहे हैं। ये प्रयास परीक्षण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक साबित हो सकते हैं।

आखिरी घटना है, श्रम कानूनों में किया गया बदलाव। इसे अनायास लागू करने की घोषणा की गई और 'वीबी जी राम जी' यानी विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गांटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक भी लाया गया। इसको भी राष्ट्रपति ने मंजूरी कर लिया है और अब यह कानून का रूप ले चुका है। हालांकि, आकलन है कि श्रम सुधारों की यह कवायद इसलिए की जा रही है, ताकि निर्यात बढ़ाए जा सकें और कृषि बाजार अमेरिकी आयात के लिए खुल सकें।

कुल मिलाकर, 2025 की तमाम आर्थिक घटनाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अनिश्चितताओं से जुड़ी हुईं थीं। देखना होगा कि नए साल में ये किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी से कितनी उम्मीदें

जुलाई विद्रोह के बाद बांग्लादेश आज जब सत्ता से संस्था और सड़क तक नेतृत्व के वैक्यूम से गुजर रहा है, तब पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के स्वनिर्वासन से अपने देश लौट आए हैं। ऐसे में, जब सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस देश को कट्टरपंथियों के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश में असफल दिख रहे हैं, तब तारिक रहमान को क्या ऐसे नेता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो उस वैक्यूम को भर सके? क्या जुलाई विद्रोह के बाद उभरे राजनीतिक दल भी तारिक रहमान को देश के भावी नेता के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे?

मोटे तौर पर माना जा सकता है कि तारिक रहमान बांग्लादेश में इस समय अकेले ऐसे नेता हैं, जिनके पास एक ऐसी पार्टी है, जिसका प्रभाव और संगठन देशव्यापी है। इसमें कोई संशय नहीं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कांडर, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी मशीनरी उनके इर्द-गिर्द संगठित है, पर तारिक रहमान न तो जुलाई विद्रोह का चेहरा रहे हैं और न उसके वैचारिक सूत्रधार। ऐसे में, वर्तमान परिदृश्य में उनकी स्वीकारोक्ति कितनी होगी, यह कहना मुश्किल है। उनकी वापसी आंदोलन से उपजी आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक अवसर मात्र है।

आंदोलित लोगों को उम्मीद थी कि मोहम्मद यूनूस शेख हसीना के हटने के बाद एक बेहतर व्यवस्था की नींव रखेंगे, मगर बांग्लादेश तो अराजकता, हिंसा और कट्टरपंथ की ओर चला गया, जिसमें आंदोलनकारी छात्रों की उम्मीदें भी बह गईं। आज यूनूस और उनकी सरकार कठघरे में है। जुलाई विद्रोह से उभरे कट्टरपंथी युवा नेता उस्मान हादी के भाई का सीधा आरोप है कि उनके भाई को सरकार से जुड़े लोगों ने ही मरवाया है, ताकि फरवरी में होने वाले चुनाव टाले जा सकें। यह स्थिति मोहम्मद यूनूस के अनुकूल नहीं है। तो क्या तारिक रहमान के अनुकूल है? संभवतः नहीं और हां भी।

नहीं इसलिए, क्योंकि तारिक रहमान पर अपराध व भ्रष्टाचार के कई आरोप रहे हैं, जिनके कारण उन्हें लंदन में लंबा निर्वासन बिताना पड़ा। हालांकि, उन्हें 2004 के ग्रेनेड हमले और जिया ऑफनेज ट्रस्ट जैसे बड़े मामलों में बरी किया जा चुका है, लेकिन पार्टी के भीतर वंशवादी नेतृत्व की आलोचना और 'नॉन टेस्टेड' नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें ट्रांजिशनल फीगर से आगे नहीं ले जाया जा सकता। इसमें कोई संशय नहीं कि यदि बीएनपी



रहीस सिंह | विदेशी मामलों के वरिष्ठ अध्याता

जीती, तो वह प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार होंगे, पर वह राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति के प्रतिनिधि बनेंगे, यह कहना अतार्किक होगा।

तारिक रहमान को आपसी भाईचारे वाला नेता कहना भी अभी जल्दबाजी होगी। भले ही ढाका की रैली में वह यह एलान करते दिखे कि जैसे देश के लोगों ने 1971 में आजादी हासिल की थी, वैसे ही एक बार फिर बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए ये लोग एकजुट होंगे। मगर

इस ऐतिहासिक तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि बीएनपी के शासन में जमात-ए-इस्लामी सत्ता में साझेदार रही थी। उस दौर में जेहादी नेटवर्क में खूब वृद्धि हुई थी और अल्पसंख्यक हिंसा के शिकार बने थे।

जो भी हो, बांग्लादेश इस समय हिंसा और अराजकता के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। मीडिया के जरिये आई तस्वीरें बताती हैं कि अराजक भीड़ के लक्ष्य कुछ संस्थान और कुछ समुदाय हैं। भीड़ में शामिल लोग

अमानवीयता के वे चेहरे हैं, जो तालिबान को भी मात दे रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी छात्रसंगठनों, धार्मिक नेटवर्कों व डिजिटल मंचों के जरिये भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ रही है। इसलिए यह भर कह देना शायद अतार्किक होगा कि सत्ता बदली है, ट्रिब्यूनल सक्रिय हुआ है, शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधी करार देकर मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है और अवामी लीग को चुनाव के लिए अयोग्य संगठन करार दे दिया गया है, बस। नहीं, यह पटकथा अधूरी है।

सच है कि बांग्लादेश न केवल शांति, बल्कि लोकतंत्र से भी अभी बहुत दूर खड़ा है। जुलाई विद्रोह के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और उनके पीछे खड़ी शक्तियों के खेल इससे भी अधिक महत्वाकांक्षाओं वाले हैं। ये स्थितियां इतनी आसानी से तारिक रहमान को एक नेता के तौर पर स्वीकार करती हुई नहीं दिखतीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रश्न : “टैरिफ से तनाव के बावजूद बढ़ता भारत” — कथन के आलोक में भारत की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा : लगभग 400 शब्द)

भूमिका

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद, टैरिफ युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत ने आर्थिक मजबूती और विकास की क्षमता का प्रदर्शन किया है।
- अमेरिका सहित विकसित देशों की टैरिफ नीतियों से चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली बनी रही।

1. टैरिफ तनाव का वैश्विक संदर्भ

- अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने से वैश्विक व्यापार प्रवाह प्रभावित।
- निर्यात, रुपये की विनिमय दर और विदेशी निवेश पर दबाव।
- आपूर्ति शृंखला में अनिश्चितता और लागत में वृद्धि।

2. भारत पर टैरिफ का प्रभाव

- कुछ निर्यात क्षेत्रों (इस्पात, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल) पर नकारात्मक असर।
- रुपये पर दबाव और अल्पकालिक पूंजी प्रवाह में अस्थिरता।
- आईटी और सेवा क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे।

3. भारत की आर्थिक मजबूती के कारण

- **मजबूत घरेलू मांग** : खपत-आधारित विकास मॉडल।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश** : युवा कार्यशील जनसंख्या।
- **विविधीकृत अर्थव्यवस्था** : कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का संतुलन।
- **मजबूत बैंकिंग प्रणाली** : एनपीए में कमी, ऋण प्रवाह में सुधार।

4. नीति-स्तरीय प्रतिक्रियाएँ

- ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।
- उत्पादन-सं-Linked प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ।
- निर्यात बाजारों का विविधीकरण (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका)।
- व्यापार समझौतों और एफटीए पर जोर।

5. विदेशी निवेश और भारत की आकर्षण शक्ति

- वैश्विक कंपनियों के लिए भारत एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र।
- स्थिर राजनीतिक वातावरण और सुधार-उन्मुख नीतियाँ।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की मजबूती।

6. चुनौतियाँ बनी हुईं

- वैश्विक मंदी का संभावित प्रभाव।
- निर्यात-निर्भर क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव।
- ऊर्जा आयात और चालू खाता घाटा।
- विकसित देशों की बदलती व्यापार नीतियाँ।

7. अवसर और आगे की राह

- वैश्विक आपूर्ति शृंखला के पुनर्गठन में भारत की भूमिका।
- हरित ऊर्जा, डिजिटल व्यापार और सेवाओं में विस्तार।
- कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन।
- बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती आर्थिक कूटनीति।

निष्कर्ष

- टैरिफ तनाव भारत के लिए चुनौती अवश्य हैं, परंतु यह उसकी विकास यात्रा में बाधक नहीं बने।
- संरचनात्मक सुधारों, मजबूत घरेलू आधार और नीति-लचीलेपन के कारण भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है।